04 - बारह वर्षों में सामाजिक न्याय की उल्लेखनीय लड़ाई

05 - बचपन को लौटाना होगा उसका खोया आसमान

A Daily News Magazine

भोपाल

शुक्रवार, 12 जून, 2026

06 - भाजपा की जिला कामकाजी बैठक में आगामी कार्य योजना...

07 - रेत के अवैध भण्डारण, परिवहन पर राजस्व, पुलिस...

भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 23, अंक 280, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

प्रसंगवश

ईरान पर ट्रंप व नेतन्याहू की रणनीति क्यों नाकाम हो रही है?

जर्मी बोवेन

डोनाल्ड ट्रंप और बिन्जामिन नेतन्याहू का मानना था कि ईरान पर जीत से पूरा मध्य-पूर्व बदल जाएगा। यह क्षेत्र बदल रहा है, लेकिन उस तरह नहीं जैसा उन्होंने सोचा था। इस्लामी गणराज्य ईरान पराजित नहीं हुआ है।

अब ख़तरा एक लंबे, थकाऊ स्थायी संकट का है, जो कभी सीधे युद्ध में बदल जाएगा और कभी उससे बाहर निकल आएगा। ईरानी शासन को पटखनी देना ट्रंप और नेतन्याहू की सोच से कहीं ज़्यादा कठिन साबित हुआ है। उनका आकलन ग़लत था और अब नतीजों पर उनका कोई नियंत्रण नहीं रहा है। ईरान का अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर गिराना इसका ताजा उदाहरण है। यानी ईरान के शासक अब भी अमेरिकियों को चोट पहुँचा सकते हैं और इस युद्ध के विजेता बनकर निकलने के अपने संकल्प से पीछे नहीं हटेंगे।

उनके लिए जीत का मतलब है, उनका अस्तित्व बने रहना और बढ़ी हुई प्रतिरोधक क्षमता - यानी रणनीतिक रूप से दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण जलमार्गों में से एक, होर्मुज़ स्ट्रेट पर नियंत्रण को मान्यता मिलना। राष्ट्रपति और उनके जनरल हेलीकॉप्टर के नुक़सान पर अपनी प्रतिक्रिया को इस तरह संतुलित करने की कोशिश करेंगे कि साफ़तौर पर नज़र ऐसा आए कि उन्हें दबाया नहीं जा सकता, लेकिन साथ ही धीमी और अब तक नाकाम रही कूटनीतिक प्रक्रिया की संभावना भी बची रहे।

ट्रंप ईरान के साथ एक समझौते पर दांव लगा रहे हैं ताकि होर्मुज़ स्ट्रेट को फिर से खोला जा सके और बड़े मुद्दों पर लंबी अवधि की बातचीत शुरू हो सके- जिसकी शुरुआत ईरान के संवर्धित यूरेनियम के भंडार और उसके व्यापक परमाणु कार्यक्रम से हो। अमेरिका में इस युद्ध को पसंद नहीं किया जा रहा और ट्रंप चाहते हैं कि कोई ऐसा रास्ता निकले, जिसे वह जीत के रूप में पेश कर सकें। यह एक कठिन चुनौती साबित हो रही है। ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बिन्जामिन नेतन्याहू एक पुराना सबक सीख रहे हैं। जब से इंसानों ने युद्ध की कला और अभिशाप खोजा है, नेताओं को पता चला है कि युद्ध शुरू करना आसान होता है, लेकिन उसे साफ़-सुथरी जीत के साथ ख़त्म करना कहीं ज़्यादा कठिन।

जब फ़रवरी के आखिरी दिन उन्होंने अपने देशों को ईरान के साथ युद्ध में झोंका, तो दोनों ने वीडियो बयान जारी किए। उनके शब्दों से यह झलक रहा था कि कोई ऐतिहासिक बदलाव आने वाला है। वह शासन, जिसने 1979 में शाह के तख्तापलट के बाद से ईरान पर राज किया था, अब अंत की ओर बढ़ रहा था।

अपने पूरे राजनीतिक जीवन में नेतन्याहू ने यही कहा है कि इजराइल के लिए असली ख़तरा ईरान से है, न कि फिलिस्तीनियों से या अपने अरब पड़ोसियों से। उन्होंने दूसरे अमेरिकी राष्ट्रपतियों को ईरान पर हमला करने के लिए साथ लाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे, ट्रंप अलग थे।

हमास के सात अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमला करने, यानी दो साल से अधिक समय से नेतन्याहू इजराइलियों से कहते रहे कि अमेरिका की मदद से उनकी सेना की ताक़त दुश्मनों को परास्त कर देगी और एक अधिक समृद्ध और सुरक्षित भविष्य लेकर आएगी। उनके अनुसार जवाब था ताक़त, न कि कूटनीति। नेतन्याहू का अंदाज़ ऐसा था, जैसे उनका समय आ गया हो। इसके विपरीत, जब सोमवार को ट्रंप ने उन्हें बेरूत पर हमला करने की योजना रद्द करने को कहा और वह कैमरों के सामने आए, तो इजराइल के प्रमुख अख़बार के स्तंभकार बेन कास्पित ने लिखा कि वे एक फुस्स हो चुके गुब्बारे जैसे दिख रहे थे।

ट्रंप को जल्द जीत की उम्मीद थी। दोनों सोच रहे होंगे कि ग़लती कहाँ हुई। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे ताक़तवर सेना है। इसराइल मध्य-पूर्व की महाशक्ति है।

उन्होंने इस्लामी शासन की दृढ़ता, निर्दयता और चालाकी को कम आँका। उनको यक़ीन था कि इसके सर्वोच्च नेता और उनके सबसे क़रीबी सहयोगियों को मारने से शासन भीतर से ढह जाएगा। उन्होंने उस शासन के खिलाफ़ सैन्य ताक़त के प्रभाव को ज़्यादा आँका जो लगभग 50 साल से बार-बार ख़तरों का सामना करता रहा है। जिसने खुद को हमले झेलने के क़ाबिल बनाया है और राष्ट्रीय सुरक्षा की ऐसी सोच गढ़ी है, जिसे उसके धार्मिक और वैचारिक विश्वास मज़बूती देते हैं।

अमेरिका के सहयोगी खाड़ी के तेल उत्पादक देश यूएई, बहरीन भारी नुक़सान झेल रहे हैं। उन्होंने अपना भविष्य खाड़ी में स्थिरता और अरबों डॉलर के कारोबार पर टिका रखा था। युद्ध उस दृष्टि को मृगतृष्णा में बदल रहा है। ईरानी शासन का मानना है कि अपने अस्तित्व की रक्षा कर और जिस आसानी से उसने होर्मुज़ स्ट्रेट बंद करके और खाड़ी के अपने अरब पड़ोसियों पर हमला करके विश्व अर्थव्यवस्था पर गला दबा दिया है, उसे अमेरिका और इसराइल के खिलाफ़ लंबी अवधि की प्रतिरोधक क्षमता में बदला जा सकता है।

वे लोग, जिन्होंने इजराइल और अमेरिका की ओर से मारे गए ईरानी नेताओं की पुरानी पीढ़ी की जगह ली है, वैचारिक रूप से अपने पूर्ववर्तियों जैसे ही हैं, लेकिन उस संघर्ष में- जिसे वे अस्तित्व का सवाल मानते हैं- उनकी जोखिम उठाने की इच्छा कहीं ज़्यादा है। उनका मानना है कि भविष्य में अमेरिका या इसराइल से होने वाले और हमलों को केवल शब्द नहीं रोक सकते। इसके बजाय वे दिखाना चाहते हैं कि ईरान पर और हमले ख़तरनाक नतीजे लेकर आएंगे। उसकी रणनीति का एक अहम हिस्सा है, लेबनान के युद्ध को खाड़ी के युद्ध से जोड़ना। ईरानी शासन का ट्रंप को संदेश है कि अगर इजराइल लेबनान पर बमबारी जारी रखता है और हिज़्बुल्लाह को नष्ट करने की कोशिश करता है, तो वह किसी भी तरह के समझौते की उम्मीद नहीं कर सकते। ट्रंप ने अप्रत्यक्ष रूप से दिखा दिया है कि वह मानते हैं कि लेबनान में जो होता है और खाड़ी में जो होता है, दोनों जुड़े हुए हैं।

सोमवार को नेतन्याहू ने कहा कि वह इस अंतरसंबंध को स्वीकार नहीं करेंगे। उनकी समस्या यह है कि ट्रंप अपने हितों और युद्ध ख़त्म करने की इच्छा को नेतन्याहू के उस संकल्प से ऊपर रखेंगे, जिसमें वह युद्ध को तब तक जारी रखना चाहते हैं जब तक यह घोषित न कर सकें कि तेहरान का इस्लामी शासन पंगु हो चुका है। नेतन्याहू ने बेरूत पर नियोजित हमले को रद्द कर दिया, लेकिन तब से इजराइल की सेना, आईडीएफ़, दक्षिणी लेबनान पर लगातार भारी हमले कर रही है।

मार्च में जब होर्मुज़ स्ट्रेट बंद हुआ, तो चेतावनी दी गई थी कि अगर जून तक यह बंद रहा तो वैश्विक आर्थिक परिणाम बेहद गंभीर होंगे।

(बीबीसी हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

सुबह सवेरे

subahsaverenews@gmail.com

facebook.com/subahsaverenews

www.subahsavere.news

twitter.com/subahsaverenews

सुप्रभात

आईने में नहीं दिखती हवा
तो क्या हुआ...!
वह भी अपनी सुगंध से
तो कभी
दुर्गंध से अपनी उपस्थिति
दर्ज कराती रहती है...
ठीक उसी तरह
बे चेहरा आदमी
आधार से अपने जिंदा होने का
सबूत देकर वोट देता है
फिर नदारद हो जाता है
जनतंत्र के पटल से
योजनाओं में अंतिम व्यक्ति की
पंक्ति में खड़ा कौन ?
तब कई हाथ खड़े होते हैं
इन बे चेहरा लोगों की
शिनाख्त का आधार न होने से
उनकी गिनती नहीं होती
बस ! उनके चेहरे पर
दिखती है उदासी की गहरी
काली लकीरें
जो दूषित हवा और पानी की
खरोंचों की तरह दिखती है
वैसे ही जैसे...
हवा अपने होने की
पहचान कराती है
सुगंध से या दुर्गंध से।

- अरुण सातले

एमपी से बीजेपी के तीनों राज्यसभा उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित

जीत का सर्टिफिकेट मिला

भाजपा के तीनों प्रत्याशी रजनीश अग्रवाल, तरुण चुग, और महेश केवट राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए, विधानसभा में उन्हें प्रमाणपत्र दिया गया। **फोटो प्रवीण वाजपेई**

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश में कांग्रेस से राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हो गया है। इसके बाद बीजेपी के तीनों राज्यसभा उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। तीनों उम्मीदवारों को विधानसभा से जीत का सर्टिफिकेट मिल गया है। इसके बाद पार्टी नेताओं ने उन्हें मिठाई खिलाकर बधाई दी है।

बीजेपी के तीनों उम्मीदवार निर्वाचित- दरअसल, मध्य प्रदेश बीजेपी ने तीन उम्मीदवारों को राज्यसभा के लिए उतारा था। इसमें रजनीश अग्रवाल, तरुण चुघ और महेश केवट थे। तीनों निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। उन्हें विधानसभा में निर्वाचन सर्टिफिकेट मिल गया है। इसके बाद उनके समर्थकों जश्न का माहौल है।

महेश केवट थे तीसरे उम्मीदवार- राज्यसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश में बीजेपी के खाते में दो ही सीट जा रही थी। तीसरे उम्मीदवार की जीत के लिए 10 वोटों की जरूरत थी।

14 उम्मीदवार निर्विरोध राज्यसभा चुनाव जीते

नई दिल्ली/ भोपाल/ जयपुर/ अहमदाबाद (एजेंसी)। 14 उम्मीदवार गुरुवार को निर्विरोध राज्यसभा चुनाव जीत गए। इनके सामने कोई और कैंडिडेट खड़ा नहीं था। इनमें 10 भाजपा और 4 कांग्रेस से हैं। चुनाव जीतने वालों में कर्नाटक से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और मीडिया व प्रचार प्रमुख पवन खेड़ा का नाम शामिल है। वहीं, राजस्थान से भाजपा के सतीश पूनिया, अलका गुर्जर और कांग्रेस के नीरज डांगी निर्विरोध राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। इसके अलावा गुजरात से भाजपा के सभी चार राज्यसभा उम्मीदवारों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया है।

कांग्रेस उम्मीदवार नटराजन के रद्द नामांकन पर चुनाव आयोग की चुप्पी

आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के खिलाफ पार्टी की याचिका पर सुनवाई शुक्रवार तक के लिए टाल दी थी। मामले पर चुनाव आयोग ने भी कोई फैसला नहीं दिया है। ऐसे में तीनों सीटों पर बीजेपी की जीत तय मानी जा रही थी। दरअसल, तीसरी

सीट के लिए कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया था। कांग्रेस के पास संख्या बल भी था, लेकिन 9 जून को नटराजन का नामांकन फॉर्म निरस्त कर दिया गया था। इसके खिलाफ बुधवार दोपहर करीब 12 बजे कांग्रेस के 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में निर्वाचन आयोग से मुलाकात की थी। कांग्रेस की शिकायत पर आयोग की तरफ से कोई बयान नहीं आया था।

कांग्रेस ने रिजल्ट पर रोक लगाने की मांग की थी

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कांग्रेस के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मामले की सुनवाई आज ही की जाए, क्योंकि नाम वापस लेने की आखिरी समय-सीमा आज दोपहर 3 बजे तक है।

खाद की कालाबाजारी की सूचना दें, इनाम पाएं

हेल्पलाइन नंबर 155253 पर देनी होगी सूचना

भोपाल (नप्र)। खरीफ सीजन की शुरुआत के साथ ही किसानों को खाद की कालाबाजारी, नकली खाद और अवैध भंडारण से बचाने के लिए प्रदेश सरकार ने नई पहल की है। अब यदि कोई किसान या आम नागरिक खाद की कालाबाजारी, अधिक कीमत पर बिक्री, नकली खाद या अवैध भंडारण की सूचना देता है और जांच में शिकायत सही पाई जाती है, तो उसे रुपए 1000 का प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाएगा।

कृषि विभाग ने पूरे मध्यप्रदेश में इन्फॉर्मर इंसेंटिव स्कीम लागू की है। योजना के तहत किसानों और आम लोगों की मदद से खाद से जुड़े अवैध कारोबार पर निगरानी रखी जाएगी।

सरकार का मानना है कि खरीफ सीजन में खाद की मांग बढ़ने के साथ कालाबाजारी और नकली खाद की बिक्री की आशंका भी बढ़ जाती है, इसलिए लोगों की भागीदारी जरूरी है।

कौन कर सकता है शिकायत?

किसान, आम नागरिक, व्यापारी या कोई भी व्यक्ति ऐसी गतिविधियों की सूचना दे सकता है। विभाग ने भरोसा दिलाया है कि शिकायतकर्ता की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।

शिकायत कैसे करें?

शिकायत सीएम किसान हेल्पलाइन 155253 पर दर्ज कराई जा सकती है। हेल्पलाइन पर कार्य दिवसों में सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक कॉल किया जा सकेगा।

कब मिलेगा इनाम?

सूचना मिलने के बाद कलेक्टर द्वारा गठित टीम जांच करेगी। जांच में शिकायत सही पाए जाने और कार्रवाई (जब्ती या दोष सिद्ध होने) की स्थिति में सूचना देने वाले को रू. 1000 का प्रोत्साहन दिया जाएगा।

इंदौर की अनादि तागड़े का चयन अंडर-19 टीम में, श्रीलंका जाएंगी

इंदौर। श्रीलंका महिला अंडर-19 टीम के खिलाफ होने वाली सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने भारतीय महिला अंडर-19 टीम की घोषणा कर दी। इस टीम में इंदौर की प्रतिभाशाली तेज गेंदबाज अनादि तागड़े को वनडे और टी20 दोनों टीमों में जगह मिली है। अनादि मध्य प्रदेश से चयनित होने वाली एकमात्र खिलाड़ी हैं।

अनादि लंबे समय से अपनी शानदार गेंदबाजी के दम पर उम्र वर्ग क्रिकेट में पहचान बना रही हैं और अब उन्हें देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। अनादि अपनी घातक गेंदबाजी से सुर्खियां बटोर चुकी हैं। महिला अंडर-19 टी20 ट्रॉफी में उन्होंने सिक्किम के खिलाफ 4 ओवर में केवल 8 रन देकर 6 विकेट झटके थे, जिसमें हैट्रिक भी शामिल थी। इस प्रदर्शन ने उन्हें देश की उभरती हुई तेज गेंदबाजों में शामिल कर दिया। अब श्रीलंका के खिलाफ आगामी सीरीज में अनादि तागड़े पर सभी की नजरें रहेंगी।

अनादि के चयन से उनके परिवार, कोचों और इंदौर के क्रिकेट प्रेमियों में खुशी की लहर है। क्रिकेट अनादि को विरासत में मिला है। उनकी मां दीप्ति तागड़े स्वयं क्रिकेटर रह चुकी हैं और उन्होंने ही बेटी को शुरुआती प्रशिक्षण दिया था। बाद में अनादि ने क्लब क्रिकेट के जरिए अपने खेल को निखारा और लगातार मेहनत के दम पर चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर खींचा।

इंदौर की यह युवा खिलाड़ी अपने प्रदर्शन से भारतीय टीम को मजबूती देने और भविष्य में सीनियर भारतीय महिला टीम में जगह बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम बढ़ाने के लिए तैयार है। अनादि के प्रेरणा स्त्रोत हार्दिक पंड्या हैं! वे इंदौर के वरिष्ठ पत्रकार और कला समीक्षक अनुराग तागड़े की बेटी हैं।

नीति आयोग की बैठक में बोले पीएम मोदी

दुनियाभर में अनिश्चितता, फिर भी भारत पूरे भरोसे के साथ आगे बढ़ रहा

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 11वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज जब पूरी दुनिया अस्थिरता और अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है, तब भी भारत पूरे आत्मविश्वास और पक्के इरादे के साथ विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है।

पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि जैसे-जैसे हम विकसित भारत के सपने की ओर बढ़ रहे हैं, केंद्र और सभी राज्यों की सामूहिक जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है।

युवाओं को ऐतिहासिक मौका और रोजगार प्राथमिकता : पीएम

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के पास इस समय युवाओं की सबसे बड़ी आबादी है। यह एक ऐसा ऐतिहासिक अवसर है जिसे हम किसी भी कीमत पर गंवा नहीं सकते। उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता युवाओं को बेहतर शिक्षा, बाजार की मांग के हिसाब से हुनर और रोजगार के नए अवसर देना होना चाहिए। पीएम मोदी ने जोर दिया कि मजबूत और सक्षम युवा ही विकसित भारत के सफर की सबसे बड़ी ताकत बनेंगे।

- **छोटे उद्योगों के लिए खुले वैश्विक रास्ते** - व्यापार को बढ़ावा देने पर बात करते हुए पीएम मोदी ने आगे कहा कि भारत ने दुनिया के कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं।

इससे भारतीय सामान के निर्यात के लिए नए रास्ते खुले हैं।

बालेन शाह और मोदी सरकार का बड़ा फैसला

भारत-नेपाल के बीच शुरू हुई डिजिटल पेमेंट सर्विस, नोट बदलने का झंझट खत्म

नई दिल्ली (एजेंसी)। नेपाल की बालेन शाह और भारत की मोदी सरकार के बीच दोनों करेंसी एक्सचेंज को लेकर बड़ा फैसला हुआ है। दोनों देश के नागरिक अब एक-दूसरे देश में बिना किसी रुकावट के डिजिटल ट्रांजेक्शन कर सकेंगे। दोनों देशों ने यूपीआई-एनपीआई क्रॉस-बॉर्डर रेमिटेंस मैकेनिज्म को आधिकारिक तौर पर शुरू कर दिया गया है।

भारत के यूपीआई और नेपाल के एनपीआई के सीधे जुड़ने से अब दोनों देशों के आम नागरिकों, प्रवासियों और व्यापारियों के लिए पैसे का लेन-देन बेहद आसान हो गया है।

भोपाल का तापमान

अधिकतम 20 °c | न्यूनतम 18°c

सुबह सवेरे

भोपाल ■ शुक्रवार, 12 जून 2026

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

संक्षिप्त समाचार

ट्रम्प की धमकी-आज रात ईरान पर करेंगे सबसे बड़ा हमला

खार्ग द्वीप का तेल-गैस कब्जाएंगे, अमेरिकी हमले में 3 भारतीयों की मौत, भारत नाराज

तेल अवीव/तेहरान/वॉशिंगटन डीसी (एजेंसी)। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने ईरान पर हमले नई धमकी दी है। ट्रम्प ने कहा कि अमेरिका गुरुवार रात ईरान पर बड़ा हमला करेगा। उनका दावा है कि ईरान की ज्यादातर सैन्य ताकत पहले ही कमजोर हो चुकी है।

ट्रम्प ने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में अमेरिका ईरान के सबसे बड़े ऑयल एक्सपोर्ट सेंटर खार्ग आइलैंड और दूसरे अहम तेल-गैस ठिकानों पर कब्जा करेगा। खार्ग आइलैंड को ईरान के तेल निर्यात का सबसे बड़ा सेंटर माना जाता है। वहीं, ओमान के पास भारतीय नाविकों वाले जहाजों पर अमेरिकी हमलों को लेकर भारत ने कड़ा विरोध दर्ज किया है।

पीओके में पाकिस्तानी सेना का हेलिकॉप्टर क्रैश

21 सुरक्षाकर्मियों के मारे जाने की खबर

इस्लामाबाद (एजेंसी)। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में बुधवार को पाकिस्तान सेना का एक एमआई-17 हेलिकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसा मुजफ्फराबाद के पास उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद हुआ। हेलिकॉप्टर में सवार सभी 21 सुरक्षाकर्मियों के मारे जाने की खबर है। हालांकि सेना ने अभी यह नहीं बताया है कि हेलिकॉप्टर में कुल कितने लोग सवार थे।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा

गृहिणियां होममेकर नहीं 'राष्ट्र निर्माता' है

वे परिवार की नींव मजबूत करती हैं, उनके काम की कीमत हर महीने 30 हजार जितनी

नई दिल्ली (एजेंसी)। देशभर में सड़क हादसों में जान गंवाने वाली गृहिणियों के परिवारों को मिलने वाले मुआवजे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि घर संभालने वाली महिलाओं को राष्ट्र निर्माता (नेशन बिल्डर) का दर्जा मिलना चाहिए। उनके काम की तुलना किसी पेशेवर से करके उनके योगदान को कम नहीं आंका जा सकता। जस्टिस संजय करोल और न्यायाधीश एन कोटिस्वर सिंह की बेंच ने कहा कि किसी हादसे में गृहिणियों की मौत होने पर, उनके द्वारा की जाने वाली परिवार की देखभाल और घरेलू काम की कीमत कम से कम 30 हजार रुपए प्रति महीना (3.6 लाख रुपए सालाना) मानी जाएगी।

चीन की छाती तक चढ़ गया भारत

हिमालय में बना दी सबसे लंबी सुरंग!

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत ने 9 जून को रणनीतिक रूप से बेहद अहम माने जाने वाले जोजिला टनल ने अपना 'फाइनल ब्रेकथ्रू' हासिल कर लिया। हिमालय के पहाड़ की चट्टानों के आखिरी हिस्सों को ब्लास्ट करके इसके दोनों सिरों को आपस में जोड़ दिया गया, जिससे लद्दाख और कश्मीर के बीच हर मौसम में और तेजी से कनेक्टिविटी का रास्ता साफ़ हो गया। इसके साथ ही टनल बनाने का काम भी पूरा हो गया, जो अक्टूबर 2020 में शुरू हुआ था। चीन के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (एलएसी) सीमा पर अक्सर तनाव के बीच इस सुरंग को भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के इतिहास में एक ऐतिहासिक उपलब्धि माना जा रहा है।

11,578 फीट ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी सिंगल ट्यूब सुरंग- समुद्र तल से 11,578 फीट की ऊंचाई पर बन रही जोजिला सुरंग इतनी ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी सिंगल-ट्यूब दोनों तरफ से आने-जाने वाली सड़क सुरंग होगी। इस 'ब्रेकथ्रू' कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, जम्मू-कश्मीर के उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा और जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला शामिल हुए। चारों तरफ जमीन से घिरे लद्दाख के लोगों की लंबे समय से यह मांग रही है कि कश्मीर और भारत के बाकी हिस्सों से साल भर संपर्क बना रहे। सर्दियों की शुरुआत में हिमालय में खतरनाक जोजिला दर्रे पर भारी बर्फबारी के कारण यह इलाका लगभग छह महीने तक कटा रहता है।

एलएसी पर भारतीय सेना को रसद और हथियार ले जाने में तेजी- एक बार इस्तेमाल के लिए खुलने के बाद, 13.15 किलोमीटर लंबी यह सुरंग पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ सीमा पर चल रहे तनाव के बीच, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (एलएसी) पर तैनात भारतीय सेना के लिए रणनीतिक और लॉजिस्टिक्स के लिहाज से भी काम आएगी।

घर में घुसकर की थी मारपीट

कोर्ट के आदेश पर दतिया में पूर्व एसएचओ समेत चार पुलिसकर्मियों पर एफआईआर

दतिया (नप्र)। एक महत्वपूर्ण न्यायिक फैसले में जेएमएफसी न्यायालय ने सिनावल के तत्कालीन थाना प्रभारी अरविंद सिंह भदौरिया सहित चार पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। यह आदेश राजघाट कॉलोनी में एक परिवार के घर में कथित तौर पर जबरन घुसकर मारपीट करने के मामले में दिया गया है।

एफआईआर करने के निर्देश- जज विजिताश्व पुष्कर ने कोतवाली पुलिस को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस मामले में तत्काल प्रकरण दर्ज किया जाए। अदालत ने 16 जून तक कार्रवाई की स्थिति रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने यह चेतावनी भी दी है कि यदि आदेश के पालन में किसी प्रकार की देरी या लापरवाही बरती जाती है, तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ न्यायालय की अवमानना और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

मार्च 2024 का है मामला- यह घटना 27 मार्च 2024 की बताई जा रही है। दतिया के रावरी निवासी युवराज सिंह बुंदेला का परिवार राजघाट कॉलोनी में किराए के मकान में रह रहा था। अधिवक्ता विवेक सिंह जाट ने अदालत को बताया कि घटना के दिन तत्कालीन एसएचओ अरविंद सिंह भदौरिया, हेड कांस्टेबल पुष्पराज सिंह जौहरिया, आरक्षक कपिल शर्मा और महिला आरक्षक पूजा सिकरवार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज करने का आदेश दिया है।

पुलिस में दर्ज कराई थी शिकायत- पीड़ित परिवार ने पहले पुलिस विभाग में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद युवराज सिंह बुंदेला ने जेएमएफसी न्यायालय में परिवाद दायर किया, जिसमें वर्दी की आड़ में कथित अपराध करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की गई थी।

केस दर्ज कर रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करेगी- कोर्ट ने आवेदन स्वीकार करते हुए कोतवाली पुलिस को तत्कालीन एसएचओ अरविंद सिंह भदौरिया, हेड कांस्टेबल पुष्पराज सिंह जौहरिया, आरक्षक कपिल शर्मा और महिला आरक्षक पूजा सिकरवार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज करने का आदेश दिया है।

कांग्रेस की विचारधारा मजबूत : राहुल गांधी

- **राहुल गांधी बोले- भाजपा-आरएसएस से लड़ने में यही सबसे सक्षम; बिखर रहीं बाकी पार्टियां**

नई दिल्ली (एजेंसी)। राहुल गांधी ने कहा कि टीएमसी जैसी पार्टियां बिखर रही हैं, जबकि कांग्रेस वैचारिक रूप से मजबूत है। उन्होंने देश की खराब आर्थिक स्थिति के लिए सरकार को कोसा और पीएम से जवाब मांगा। इसके साथ ही उन्होंने पांच राज्यों में आदिवासियों के अधिकार छीनकर पसंदीदा उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया।

दिल्ली में कांग्रेस की एक बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के नेताओं में नया जोश भरा।

उन्होंने कहा कि आज के समय में कांग्रेस ही देश की एकमात्र ऐसी पार्टी है, जो विचारधारा के स्तर पर मजबूती से खड़ी है और बिल्कुल नहीं टूट रही है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि इसी वैचारिक मजबूती के कारण कांग्रेस ही आरएसएस और भाजपा का मुकाबला करने के लिए सबसे सही और सक्षम पार्टी है।

अर्थव्यवस्था की हालत खराब, पीएम दें जवाब

इस बैठक में कांग्रेस के सभी बड़े पदाधिकारी, महासचिव और राज्यों के अध्यक्ष शामिल हुए थे। सूत्रों के अनुसार, राहुल गांधी ने भरोसा जताया कि कांग्रेस आने वाले दो साल में और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। राहुल गांधी ने देश की आर्थिक स्थिति पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत नाजुक मोड़ पर है। इसके लिए उन्होंने अंतरराष्ट्रीय कारणों को नहीं, बल्कि सीधे तौर पर केंद्र सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने मांग की कि इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री को खुद जवाब देना चाहिए।

दिल्ली में कांग्रेस का लोकतंत्र बचाओ अभियान तेज, राष्ट्रपति से मुलाकात का समय मांगा : जीतू पटवारी

भोपाल। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा और जनता के मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी अपने संघर्ष के अगले चरण में प्रवेश कर रही है। उन्होंने बताया कि कल मध्य प्रदेश कांग्रेस के सभी विधायक दिल्ली पहुंचेंगे। राष्ट्रपति महोदय से मुलाकात के लिए समय मांगा गया है और समय मिलने की प्रतीक्षा की जा रही है।श्री पटवारी ने कहा कि कल कांग्रेस पार्टी मीडिया के समक्ष पूरे घटनाक्रम और अपने पक्ष को विस्तार से रखेगी, जिसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश में बढ़ती महंगाई, पेट्रोल-डीजल की कीमतों में वृद्धि, युवाओं के भविष्य से जुड़े पेपर लीक जैसे मामलों और किसानों की समस्याओं पर सरकार जवाबदेही से बचने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि किसान खाद और उर्वरक जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए परेशान हैं, देश की अर्थव्यवस्था चुनौतियों का सामना कर रही है और विदेश नीति से लेकर आम जनता के जीवन से जुड़े कई मुद्दों पर असंतोष का माहौल है। इन सभी परिस्थितियों के लिए केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियां जिम्मेदार हैं।श्री जीतू पटवारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जनता की आवाज को मजबूती से उठाती रहेगी और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए अपना संघर्ष जारी रखेगी।

राजकुमार पटेल की सेवानिवृत्ति पर मंत्रालय में अखण्ड रामायण 15 को

भोपाल। मंत्रालय सेवा अधिकारी कर्मचारी संघ के कार्यकारी अध्यक्ष तथा राजकुमार पटेल अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर 30 जून को सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। पटेल 40 वर्ष की सुदीर्घ शासकीय सेवा के बाद सेवानिवृत्त हो रहे हैं। राजकुमार पटेल एक ईमानदार, निस्वार्थ, जुझारू, संघर्षशील कर्मचारी नेता के साथ साथ एक उत्कृष्ट शासकीय सेवक भी रहे हैं। उत्कृष्ट,कर्तव्यनिष्ठ,कार्यकुशल शासकीय सेवकों को मध्यप्रदेश शासन द्वारा दिया जाने वाला 1 लाख रुपए का देवीप्रसाद शर्मा पुरस्कार भी राजकुमार पटेल को मिल चुका है। पटेल , नारायण प्रसाद शर्मा, सत्यनारायण तिवारी, देवीप्रसाद शर्मा जैसे लीजेंडरी कर्मचारी नेताओं की टीम का हिस्सा रह चुके हैं। श्री पटेल लघुवेतन कर्मचारी संघ के उपप्रांताध्यक्ष रह चुके हैं।

राजकुमार पटेल की सेवानिवृत्ति के उपलक्ष्य में 15 जून सोमवार को मंत्रालय वल्लभ भवन के गेट क्रमांक 06 के पास स्थित गणेश मंदिर में अखंड रामायण पाठ और विशाल झरा भंडारे का आयोजन किया गया है। अखण्ड रामायण पाठ 14 जून से शुरू हो जायेगा जिसकी पूर्णाहुति 15 जून को 11 बजे तक होगी और 12 बजे से 04 बजे तक झरा भंडारा चलेगा।

17 साल, 1600 करोड़ का खर्च, अमेरिकी मशीनें हुईं फेल, मजदूरों ने दी शहादत, तब तैयार हुई स्लीमानाबाद टनल

कटनी (नप्र)। मध्य प्रदेश के कटनी जिले के एक छोटे से कस्बे स्लीमानाबाद में पिछले 17 वर्षों से चल रहा देश का सबसे जटिल और चुनौतीपूर्ण इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। पहाड़ों को काटकर, जान जोखिम में डालकर और कई भारी विदेशी मशीनों के टूटने के बाद आखिरकार भारत की सबसे लंबी सिंचाई सुरंग स्लीमानाबाद टनल का निर्माण कार्य पूरा होने वाला है। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के मुताबिक, 11.95 किलोमीटर लंबी इस सुरंग का महज 92 मीटर हिस्सा ही अब खोदा जाना बाकी है, जिसे इसी महीने के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा।

टूट जाएगा पौराणिक मिथक- इस टनल की सफलता के पीछे एक दिलचस्प पौराणिक पहलू भी है। मान्यताओं के अनुसार, एक ही अमरकंटक (मैकाल) की पहाड़ियों से निकलने वाली नर्मदा और सोनभद्र कभी अलग न मिलने वाले प्रेमी हैं, जो विपरीत दिशाओं में बहते हैं। लेकिन इस 11.95 किमी लंबी टनल के जरिए अब नर्मदा का पानी विंध्य पर्वतमाला के नीचे से होते हुए सोन बेसिन में प्रवेश करेगा। इस ऐतिहासिक टनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा अगस्त या सितंबर महीने में किए जाने की उम्मीद है।

अमेरिकी मशीनें भी टेक चुकी थीं घुटने- स्लीमानाबाद के नीचे की भूगर्भीय संरचना यानी जियोलॉजी इतनी कठिन थी कि संगमरमर, चूना पत्थर, डोलोमाइट और स्लेट की परतों ने साल 2011 में आयात की गई भारी-भरकम अमेरिकी रोबिन्स टनल बोरिंग मशीन को तोड़ दिया था। शुरुआती 1.6 किमी की खुदाई में ही इंजीनियरों को साढ़े छह साल लग गए। बाद में जर्मन मशीन की मदद ली गई। इस बेहद खतरनाक काम के दौरान जहरीली गैसों, अचानक पानी के रिसाव और मिट्टी धंसने से कई मजदूरों ने अपनी जान भी गंवाई।

बिहार पहुंचा मानसून, 8 दिन में 17 राज्य कवर

- **2-3 दिन में झारखंड-छत्तीसगढ़ पहुंचेगा, यूपी-बिहार में आंधी और बिजली गिरने से 9 की मौत**

पटना/भोपाल/जयपुर/लखनऊ/ (एजेंसी)। मानसून ने गुरुवार को बिहार में एंट्री कर ली है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी यह आगे बढ़ गया है। 4 जून को केरलम में एंट्री के बाद से मानसून 8 दिन में 17 राज्यों तक पहुंच चुका है। अगले 2-3 दिनों इसके में उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा पहुंचने की संभावना है। बिहार के 11 जिलों में आज सुबह से आंधी-बारिश हो रही है। खगड़िया में बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग झुलस गए हैं। पटना, बक्सर, सुपौल समेत 5 जिलों में घने बादलों से अंधेरा छा गया। लोगों को गाड़ियों की लाइट जलाकर चलना पड़ा। यूपी में आंधी से एक पेट्रोल पंप की छत उड़ गई। चित्रकूट में 4.5 करोड़ रुपए के ऑडिटोरियम की छत भी उड़ गई। बरेली, इटावा, सीतापुर और फिरोजाबाद में आंधी-तूफान से 4 लोगों की मौत हुई। पंजाब के मानसा में तेज आंधी के दौरान लोहे का गेट गिरने से 9 साल के बच्चे की मौत हो गई।

इधर, गुजरात को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में प्री-मानसून का असर है। दिल्ली में खराब मौसम के चलते 2 फ्लाइट जयपुर डायवर्ट करनी पड़ीं। राजस्थान के कई इलाकों में आंधी के साथ बारिश हुई।

चमोली में सड़क हादसा

कैल नदी में बोलेरो वाहन गिरने से 4 की मौत, 3 घायल

गोपेश्वर (चमोली) (एजेंसी)। जनपद चमोली के दूरस्थ विकासखंड देवाल से एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। गुरुवार को कुंनार-गेस मोटर मार्ग पर एक वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में लुढ़कते हुए सीधे कैल नदी में जा गिरा। इस भीषण हादसे में चार लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हैं। वाहन में कुल सात लोग सवार थे।

तृणमूल कांग्रेस का संकट गहराया, ममता को चौथा झटका

चार दिन में 4 इस्तीफे, शत्रुघन सिन्हा बोले में दीदी के साथ हूँ

कोलकाता (एजेंसी)। बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी पराजय के बाद तृणमूल कांग्रेस का संकट लगातार गहराता जा रहा है। पार्टी के भीतर शुरू हुई बगावत विधानसभा से लेकर संसद तक पहुंच चुकी है। गुरुवार को राज्यसभा सांसद प्रकाश चिक बड़ाईक और अभिनेत्री-सांसद कोयल मल्लिक ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही पिछले चार दिनों में राज्यसभा से इस्तीफा देने वाले तृणमूल सांसदों की संख्या चार हो गई है। इससे पहले सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव भी उच्च सदन की सदस्यता छोड़ चुके हैं। वहीं शत्रुघन सिन्हा ने मीडिया से कहा में ममता दीदी के साथ हूँ उन्हे अकेला नहीं छोड़ सकता।

कल्याण बनर्जी का अल्टीमेटम- ममता मुझे चुनें या अभिषेक को: ममता बनर्जी के सबसे करीबी सांसद कल्याण बनर्जी की भी गुरुवार को नाराजगी सामने आई। उन्होंने कहा कि ममता को तय करना होगा कि वे मेरे साथ हैं या अभिषेक बनर्जी के साथ। अभिषेक को सीनियर नेताओं का सम्मान करना नहीं आता। वह बहुत अहंकारी हैं। इसी वजह से पार्टी बर्बाद हुई है। उन्होंने कहा, अगर ममता दीदी को अभिषेक बनर्जी पर ही निर्भर रहना है, तो उनके साथ रहें और मुझे छोड़ दे।

दावा- 20 लोकसभा सांसद अलग गुट बना चुके: इससे पहले टीएमसी की बागी सांसद काकोली घोष ने दावा किया था कि 20 लोकसभा सांसद अलग गुट बना चुके हैं। वहीं, बंगाल के 80 में से 58 टीएमसी विधायक अलग गुट बना चुके हैं।

फालता में पुलिस ने जहांगीर खान को हाफ पैंट में घुमाया: बंगाल के दुर्गापुर में गुरुवार को टीएमसी (तृणमूल कांग्रेस) नेता सुकुमार दत्ता को भ्रष्टाचार और जबरन वसूली जैसे कई आरोपों में गिरफ्तार किया गया। जब पुलिस उन्हें थाने से अदालत ले जा रही थी, तब भीड़ ने उन पर अंडे फेंके। वहीं, पश्चिम बंगाल के फलता में गुरुवार को टीएमसी नेता जहांगीर खान हाफ पैंट (निक्कर) में पुलिस के साथ घूमते नजर आए।

ईरानी डेरे में निशातपुरा पुलिस की दबिश

● इनामी बदमाश फरारी काटता मिला, निगरानीशुदा भी गिरफ्तार ● लूट-चोरी सहित कई मामलों में वांटेड हैं आरोपी

भोपाल (नप्र)। भोपाल में फरार अपराधियों और वारंटियों की धरपकड़ के लिए निशातपुरा पुलिस ने एक बार फिर ईरानी डेरा अमन कॉलोनी में दबिश दी। करीब 40 पुलिसकर्मियों की टीम के साथ की गई इस कार्रवाई से इलाके में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 17 हजार रुपए के इनामी निगरानी बदमाश सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फरार इनामी बदमाश ने पुलिस को बताया कि वह डेरे में लंबे समय से फरारी काट रहा है। पुलिस कमिश्नर संजय सिंह के निर्देश पर 10 जून की शाम ईरानी डेरे में विशेष सर्चिंग और रेड कार्रवाई की गई। पुलिस टीम ने संदिग्धों की तलाश के साथ ही फरार आरोपियों और वारंटियों की जानकारी जुटाई। जिसके बाद कार्रवाई शुरू की। कार्रवाई के दौरान निशातपुरा थाने के निगरानी बदमाश सालिग उर्फ रेहान ईरानी को पकड़ा गया। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ भोपाल सहित अलग-अलग जिलों में लूट, चोरी, जालसाजी, मारपीट और हत्या के प्रयास जैसे 24 गंभीर अपराध दर्ज हैं।

तीन जिलों की पुलिस को थी तलाश

आरोपी पर अलग-अलग मामलों में 17 हजार का इनाम घोषित था। इसमें थाना रानीपुर जिला बैतूल के प्रकरण में 10 हजार, कोतवाली रायसेन के मामले में 5 हजार और थाना पिपलानी भोपाल के प्रकरण में 2 हजार का इनाम शामिल है। आरोपी के खिलाफ न्यायालय से गिरफ्तारी वारंट भी जारी था।

ज्योतिर्लिंग-द्वारका दर्शन के लिए 'भारत गौरव' ट्रेन 11 जुलाई को

10 रात-11 दिन के पैकेज में रेल यात्रा, भोपाल समेत कई स्टेशनों से मिलेगी सुविधा

भोपाल (नप्र)। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम एक बार फिर विशेष पहल लेकर आया है। 'भारत गौरव पर्यटक ट्रेन' के जरिए श्रद्धालुओं को ज्योतिर्लिंगों के साथ पश्चिम भारत के प्रमुख तीर्थों के दर्शन का सुनहरा अवसर मिलेगा। यह ट्रेन 11 जुलाई को रीवा से रवाना होगी और भोपाल मंडल के कई प्रमुख स्टेशनों से यात्री इसमें सवार हो सकेंगे। पश्चिम मध्य रेलवे के अनुसार यह ट्रेन सतना, मैहर, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, इटारसी, रानी कमलापति स्टेशन, भोपाल, शुजालपुर और उज्जैन सहित कई स्टेशनों पर ठहरेगी। इससे मंडल के यात्रियों को अपने नजदीकी स्टेशन से ही यात्रा शुरू करने की सुविधा मिलेगी। इस आध्यात्मिक यात्रा में श्रद्धालुओं को द्वारका स्थित द्वारकाधीश मंदिर, सोमनाथ मंदिर, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग तथा ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन कराए जाएंगे। पूरी यात्रा लगभग 10 रात और 11 दिन की होगी।

ठहरने की व्यवस्था, भोजन भी मिलेगा

आईआरसीटीसी द्वारा तैयार इस टूर पैकेज में यात्रियों को रेल यात्रा के साथ ठहरने की व्यवस्था, भोजन, स्थानीय परिवहन, दर्शनीय स्थलों का भ्रमण, यात्रा बीमा, ऑन-बोर्ड सुरक्षा और टूर एस्कॉर्ट जैसी सुविधाएं एक ही पैकेज में उपलब्ध कराई जाएंगी। अलग-अलग श्रेणियों में किराए निर्धारित किए गए हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग इस धार्मिक यात्रा का लाभ उठा सकें।

यात्रा में शामिल होने के इच्छुक श्रद्धालु आईआरसीटीसी की आधिकारिक पर्यटन वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा संबंधित रेलवे स्टेशनों और आईआरसीटीसी कार्यालयों से भी विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

भोपाल को सिलेंडर फ्री बनाने का प्लान

4 बड़ी कॉलोनी में 100 प्रतिशत पीएनजी कनेक्शन देने पर फोकस, चार इमली को भी जोड़ा

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश में पिछले 3 महीने से LPG संकट चल रहा है। भोपाल में भी यह संकट बरकरार है। कई एजेंसियों पर सिलेंडर की बुकिंग को लेकर लोग परेशान हैं। बुधवार को ही एक एजेंसी पर हंगामा हुआ। ऐसे में अब खाद्य विभाग भोपाल को सिलेंडर फ्री बनाने की कवायद में जुट गया है। जिन इलाकों में पीएनजी (पाइप्ड नेचुरल गैस) लाइन बिछ चुकी है, उन्हें अब सिलेंडर नहीं दिए जाएंगे। इसे लेकर प्लान भी तैयार किया गया है।

फूड कंट्रोलर चंद्रभान सिंह जादौन ने बताया कि भोपाल में थिंक गैस के जरिए पीएनजी कनेक्शन दिए जा रहे हैं। ये लाइन मिसरोद से शुरू हुई है और होशंगाबाद रोड के दोनों ओर की कॉलोनियों को कवर किया गया है। बावड़ियाकलां, सलैया, अयोध्या बायपास, अवधपुरी, साकेत नगर के अधिकांश घरों में कनेक्शन हो चुके हैं। वहीं, चार इमली में भी काम चल रहा है।

अब तय किया है कि जिन क्षेत्रों में लाइन बिछ रही है, वहां 100 प्रतिशत कनेक्शन देने के बाद आगे की कॉलोनी में काम शुरू किया जाए। इसलिए 4 बड़ी कॉलोनियों को लिस्टेड किया है। इनमें बावड़ियाकलां स्थित केराल केनसिप, अवधपुरी स्थित सौम्या पार्कलैंड, अयोध्या बायपास स्थित सागर लैक व्यू होम्स और सलैया स्थित आकृति ग्रीन शामिल हैं।

172 कॉलोनी के सामने बिछी लाइन- फूड कंट्रोलर जादौन ने बताया कि थिंक गैस कंपनी ने होशंगाबाद रोड के दोनों ओर समेत कुल 172 कॉलोनियों में गैस लाइन बिछाई है। यहां लोगों के अप्लाई करने के बाद कनेक्शन दिए जा रहे हैं। कटारा समेत कई कॉलोनियों से लोग आवेदन करने भी लगे हैं। दूसरी ओर, तय किया है कि चार-चार

कॉलोनियों पर फोकस किया जाए। यहां पर 100 प्रतिशत कनेक्शन देने के बाद अगली चार कॉलोनियां लिस्टेड करेंगे। ताकि, काम जल्दी हो सके। निर्धारित अवधि के बाद एलपीजी कनेक्शन बंद कर दिए जाएंगे।

बड़े संस्थानों को भी पीएनजी से जोड़ेंगे- फूड कंट्रोलर जादौन ने बताया कि होटल-रेस्टोरेंट व अन्य बड़े संस्थानों को भी पीएनजी से जोड़ेंगे। बड़ी बिल्डिंग में भी कनेक्शन दिए जा रहे हैं।

इसलिए पीएनजी कनेक्शन पर फोकस

अमेरिका-ईरान युद्ध के बाद ईंधन संकट आ गया। एमपी में भी तीन-चार महीने से घरेलू गैस की किल्लत है। शुरुआती दिनों में आम से लेकर खास तक गैस की किल्लत से जूझते हुए नजर आए। भोपाल में भी आपूर्ति कम और खपत ज्यादा रही। हर रोज 12 से 14 हजार सिलेंडर तक बुकिंग हुई, जबकि सप्लाई 9-10 हजार ही रही। संकट के बीच ही कई मंत्री और अफसरों के यहां भी सिलेंडर कमी हो गई। इस संकट के बाद अब वीआईपी इलाकों में भी गैस की लाइन बिछाने का आइडिया आया है। चार इमली और 74 बंगला में काम की शुरुआत होने के बाद उन क्षेत्रों पर फोकस किया जा रहा है, जिनके पास से पाइप लाइन गुजरी हो।

होशंगाबाद रोड पर सबसे ज्यादा कनेक्शन

पीएनजी के लिए थिंक गैस कंपनी ने होशंगाबाद रोड पर भूमिगत लाइन बिछाई है। इसके जरिए आसपास की कॉलोनियों के घरों में गैस कनेक्शन दिए गए हैं। इनकी संख्या करीब 43 हजार है। अफसरों का कहना है कि भविष्य में पुराने शहर की ओर भी काम शुरू होगा। कई बड़े इलाके कवर किए जाएंगे। ताकि, घर-घर गैस पाइप लाइन के जरिए पहुंचाई जा सके। जिससे आम लोगों को गैस के लिए परेशान न होना पड़े।

चार इमली-74 बंगला में भी काम, यहीं 75 प्रतिशत से ज्यादा मंत्री, आईएएस-आईपीएस के बंगले

भोपाल के दो सबसे बड़े पॉश इलाके चार इमली और 74 बंगला में गैस की भूमिगत लाइन बिछ रही है। ये दोनों इलाके एमपी के सबसे वीआईपी है। यही पर 75 प्रतिशत से ज्यादा मंत्री, सीनियर आईएएस और आईपीएस के बंगले हैं। अधिकांश हिस्से में लाइन बिछाने का काम पूरा हो चुका है। कुछ दिन बाद बंगलों पर कनेक्शन दिए जाने शुरू होंगे।

गांजे के साथ तस्कर गिरफ्तार

नशा मुक्ति अभियान के तहत कार्रवाई, आरोपी पर पहले से दर्ज हैं कई अपराध

भोपाल (नप्र)। भोपाल की टीला जमालपुरा थाना पुलिस ने नशा मुक्ति अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए गुरुवार को एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 1.267 किलो अवैध गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत करीब 30 हजार रुपए बताई जा रही है।

पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के दौरान मुखबिर से सूचना मिली थी कि हरिजन बस्ती की पानी टंकी के पास एक व्यक्ति गांजा लेकर खड़ा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और संदिग्ध को पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम शाहिद खान (47) निवासी करीम बक्स कॉलोनी भोपाल बताया। पुलिस ने जब उसके पास मौजूद ग्रे रंग के बैग की तलाशी ली तो उसमें गांजा मिला। पुलिस ने आरोपी से गांजा रखने के संबंध में वैध दस्तावेज मांगे, लेकिन वह कोई लाइसेंस या अनुमति पत्र पेश नहीं कर सका। इसके बाद मादक पदार्थ को जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।

आरोपी पर पहले से दर्ज हैं मामले- पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी शाहिद खान के खिलाफ पहले से लूट, आबकारी एक्ट और एनडीपीएस एक्ट सहित कई अपराध दर्ज हैं। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि वह गांजा कहां से लाया था और इसे किसे सप्लाई करने वाला था।

आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

भांजे ने किया रेप, परेशान मामी ने खाया जहर

पति से शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होने से आहत थी, पुलिस ने दर्ज किया केस

भोपाल (नप्र)। राजधानी भोपाल के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली 33 वर्षीय महिला ने अपने ही भांजे पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि आरोपी घर में घुसकर उसके साथ कई बार गलत काम करता रहा। परेशान होकर उसने जहरीला पदार्थ खा लिया। अस्पताल में इलाज के दौरान दिए गए बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार पीड़िता मिसरोद इलाके के एक गांव में अपने पति के साथ रहती है। उसका पति सब्जी का काम करता है और रोजाना सब्जी खरीदने के लिए मंडीदीप की मंडी जाता है। आरोपी भी उसी गांव में पीड़िता के घर के पास रहता है। महिला के बयान के मुताबिक 5 जून को आरोपी पति की गैर मौजूदगी में घर में घुस आया और उसके साथ जबरदस्ती की। इसके बाद आरोपी कई बार इसी तरह की हरकत करता रहा। पीड़िता ने इसकी जानकारी अपने पति और परिजनों को दी, लेकिन आरोप है कि कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया। आरोपी को समझाइश तक नहीं दी गई।

परेशान होकर उठाया आत्मघाती कदम- पीड़िता ने बताया कि आरोपी की हरकतें लगातार बढ़ती जा रही थीं। शिकायतों के बावजूद परिवार वाले आरोपी को कुछ नहीं कहते थे। इससे वह मानसिक रूप से परेशान हो गई और 9 जून को जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ने पर परिजनों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां उसने पूरे मामले की जानकारी दी। पुलिस ने पीड़िता के बयानों के आधार पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म की धाराओं में केस दर्ज किया है। फिलहाल आरोपी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस टीम दबिश दे रही है। मामले की जांच जारी है।

छत्तीसगढ़ के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना का किया अध्ययन

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के क्रियान्वयन संबंधी जानकारी लेने और इसमें विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिये छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाई कार्पोरेशन के अधिकारियों का एक दल मध्यप्रदेश भ्रमण पर है। इस दल ने गुरूवार को खाद्य संचालनालय में अधिकारियों से योजना की कार्य प्रणाली, परिवहन व्यवस्था, आईटी आधरित मॉनीटरिंग प्रणाली, संबंधित विभागों के बीच

समन्वय, हित धारकों की भूमिका तथा खाद्यान वितरण व्यवस्था में योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में जानकारी ली। अपर संचालक खाद्य श्री एचएस परमार एवं अन्य अधिकारियों ने योजना के क्रियान्वयन के संबंध में पॉवर प्वाइंट प्रेजेंटेशन दिया। छत्तीसगढ़ के दल में सहायक महाप्रबंधक आईटी एवं उपार्जन श्री महेन्द्र साहू, उप सहायक महाप्रबंधक परिवहन श्री मनोज वर्मा, उप सहायक महाप्रबंधक सार्वजनिक वितरण प्रणाली श्री त्रिनाधा रेड्डी, वरिष्ठ सलाहकार श्री सुशील तिवारी और सलाहकार श्री संदीप हलदर शामिल हैं।

मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत प्रदाय केन्द्र से उचित मूल्य दुकानों तक राशन सामग्री के परिवहन का कार्य परिवहनकर्ता ठेकेदार के स्थान पर बेरोजगार युवकों के माध्यम से कराकर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने के लिये मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना नवाचार के रूप में लागू की गई है। इसमें लगभग 900 परिवहन कर्ता हैं। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजनांतर्गत ऋण स्वीकृति से 7.5 मीट्रिक टन क्षमता के वाहन उपलब्ध कराएँ गए हैं। वाहनों के लिये राज्य सरकार द्वारा 1.25 लाख रूपये प्रति वाहन मार्जिन मनी और 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाता है। वाहनों से प्रतिमाह लगभग 3,000 क्विंटल राशन सामग्री का परिवहन किया जा रहा है। योजना में बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने के साथ सामग्री का परिवहन भी त्वरित गति से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के वाहनों में जीपीएस के माध्यम से स्टेट लेवल कमांड कंट्रोल सेंटर से मॉनीटरिंग की जाती है।

नगर निगम के टैंकर ने कई वाहनों को रौंदा, 4 घायल भीड़ ने टैंकर में की तोड़फोड़

इंदौर (नप्र)। इंदौर के पटेल ब्रिज पर गुरुवार दोपहर नगर निगम का पानी का टैंकर बेकाबू हो गया। टैंकर को अपनी ओर आता देख लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। अनियंत्रित टैंकर ने कई कारों और बाइकों को टक्कर मार दी, जिससे 4 लोग घायल हो गए। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक हादसा टैंकर के ब्रेक फेल होने से हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि टैंकर अचानक अनियंत्रित हो गया और सड़क पर आगे बढ़ते हुए वाहनों को टक्कर मारता चला गया। इससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई। हादसे से नाराज लोगों ने टैंकर में तोड़फोड़ कर दी।

उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने भगवान बुद्ध के परम शिष्यों श्री सारिपुत्र एवं श्री महामौद्गल्यायन के पवित्र अस्थि कलशों के मंगोलिया विहार (मंगोलिया यात्रा) से भोपाल आगमन समारोह को संबोधित किया।

महिला बंदियों के पुनर्वास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना हमारी प्राथमिकता : आयोग अध्यक्ष श्रीमती यादव

राज्य महिला आयोग ने केंद्रीय जेल भोपाल का किया निरीक्षण

भोपाल (नप्र)। सुधार गृह केवल दंड का स्थान नहीं, बल्कि व्यक्तित्व निर्माण, आत्मविश्वास और पुनर्वास का केंद्र होना चाहिए। महिला बंदियों को सम्मानजनक वातावरण, आवश्यक सुविधाएं और कौशल विकास के अवसर उपलब्ध कराना समाज और शासन दोनों की जिम्मेदारी है। यह बात मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती रेखा यादव ने केंद्रीय जेल भोपाल के निरीक्षण के दौरान कही। उन्होंने कहा कि आयोग यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि प्रत्येक महिला को उसके अधिकार, सम्मान और न्याय मिले।

राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती यादव एवं सदस्य श्रीमती साधना स्थापक ने महिला बंदियों से संवाद कर उनकी समस्याओं, आवश्यकताओं और पुनर्वास संबंधी व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त की। आयोग ने जेल प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का जायजा लिया।

आयोग ने महिला वार्ड, चिकित्सालय, रसोई घर, पुस्तकालय, सांस्कृतिक कक्ष, आर्ट एवं क्राॅफ्ट सेंटर तथा ब्यूटी पार्लर का अवलोकन किया। सांस्कृतिक

कक्ष में महिला बंदियों द्वारा संचालित ऑर्केस्ट्रा दल ने भजन प्रस्तुत किए। आयोग की अध्यक्ष एवं सदस्य ने ऑर्केस्ट्रा की सराहना करते हुए इसे सकारात्मक मानसिक विकास और सामाजिक पुर्नस्थापन की दिशा में प्रभावी पहल बताया।

महिला बंदियों से संवाद के दौरान उनकी दिनचर्या, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, कौशल विकास कार्यक्रमों और पुनर्वास गतिविधियों से जुड़ी जानकारी प्राप्त की। आयोग ने बंदियों द्वारा आर्ट एवं क्राॅफ्ट सेंटर में तैयार किए गए विभिन्न उत्पादों का अवलोकन भी किया। आयोग की अध्यक्ष श्रीमती यादव ने महिला बंदियों की रचनात्मकता, आत्मविश्वास और कौशल की प्रशंसा करते हुए कहा कि ऐसे प्रयास उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के साथ समाज में नई पहचान बनाने का अवसर प्रदान कर रहे हैं।

राज्य महिला आयोग के सचिव श्री सुरेश तोमर, केंद्रीय जेल भोपाल के अधीक्षक श्री राकेश भांगरे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

संपादकीय

भाजपा का दांव और कई सवाल

मध्यप्रदेश से राज्यसभा की तीनों सीटें निर्विरोध जीतने का भाजपा भले ही जश्न मना रही हो, लेकिन इस जीत की नैतिकता और पवित्रता पर प्रश्नचिन्ह हमेशा रहेगा। क्योंकि यदि येन- केन- प्रकारेण चुनाव जीतना ही नैतिकता है तो भाजपा इसका श्रेय ले सकती है, लेकिन जिस तरह से और जिस कारण से कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त हुआ, उसकी गूंज दूर तक सुनाई देगी। जो कुछ घटनाक्रम घटा, उससे कहीं न कहीं यह संदेश गया है कि चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट की रवैया कुछ ऐसा रहा है कि जिससे भाजपा को फायदा हो। भले ही इसे प्रमाणित करना मुश्किल हो। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन क्यों कर रद्द हुआ, वह नियमानुसार था या नहीं, अथवा इसमें नियमों की गलत व्याख्या की गई, इसकी मीमांसा तो अब कोर्ट में होगी। लेकिन कड़वा सच यही है कि समुचित तालमेल और एकजुटता के अभाव में कांग्रेस अपनी लगभग जीती जिताई सीट गंवा बैठी है। यह कांग्रेस के सबसे बड़े नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के लिए भी बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि मीनाक्षी नटराजन को राज्य का टिकट उन्हीं की पसंद के चलते दिया गया था। मीनाक्षी यूं तो मप्र के मंदसौर की ही हैं, लेकिन लंबे समय से दिल्ली की राजनीति कर रही हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस का लोकसभा में एक भी सांसद न होने के कारण मप्र में कई नेता हैं, जो राज्यसभा जाने के लिए इच्छुक थे। इसके लिए लॉबिंग भी जारी थी। लेकिन आलाकमान ने मीनाक्षी को टिकट दे दिया। इसको लेकर पार्टी में आम सहमति नहीं दिखाई दी। शायद यही कारण है कि एक गुट मीनाक्षी को हरवाने के लिए भीतर ही भीतर सक्रिय हो गया। इस संभावना के पीछे वास्तविकता यह भी है कि तेलंगाना जैसे राज्य में बीजेपी अभी भी बहुत बड़ी राजनीतिक ताकत नहीं है। ऐसे में पूर्व में भी कांग्रेस से प्रभारी रही मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ किसी कांग्रेसी द्वारा ही दायर किया गए निजी परिवाद और उस मामले में मीनाक्षी नटराजन को जारी सम्मन की जानकारी किसी भाजपाई को हो, इसकी संभावना बहुत कम है। जाहिर है कि मीनाक्षी का नाम घोषित होते ही कांग्रेस के स्तर पर ही किसी ने सारी जानकारी जुटाकर बीजेपी तक पहुंचाई और यह जानकारी पुख्ता होने के बाद भी भाजपा ने तीसरा प्रत्याशी उतारने का फैसला आधी रात को किया। एक प्रत्याशी को जीतने के लिए 58 वोटों की जरूरत थी। भाजपा के पास अपने दो प्रत्याशियों को जिताने के बाद भी 48 विधायक अतिरिक्त थे। वो चाहती तो साम-दाम-दंड-भेद से ऐसे में कांग्रेस के 10 वोटों को 'मैनेज' करके वह तीसरा प्रत्याशी भी जिता लेती। इसकी कोशिशें भीतर ही भीतर चल भी रही थी। सोशल मीडिया में यह चर्चा रही कि कांग्रेस विधायकों को खरीदने पांच-पांच करोड़ रु. की बोली लग रही है। इसके चलते कांग्रेस ने अपने विधायकों को तेलंगाना शिफ्ट करने का प्लान भी बना लिया था। जो पूरा घटनाक्रम बदल जाने के कारण उड़ भी न सके। इस पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग केन्द्रीय स्तर पर भी हो रही थी।

मीनाक्षी नटराजन को लेकर जो प्रमाण मुहैया कराए गए थे, उसकी जांच की गई। पुख्ता पाए जाने पर नामांकन पत्रों की जांच के दिन उन्हें निर्वाचन अधिकारी के समक्ष पेश किया गया। निर्वाचन अधिकारी ने इस बारे में सुनवाई के दौरान मीनाक्षी नटराजन से सवाल भी किए, लेकिन वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सकीं। परिणामस्वरूप उनका नामांकन खारिज किया। इसका कांग्रेस ने सड़कों पर विरोध भी किया। चुनाव आयोग भी गए। सुप्रीम कोर्ट में भी दस्तक दी। लेकिन तत्काल राहत नहीं से नहीं मिली। वैसे कांग्रेस में इस तरह की भीतरी दगाबाजी का इतिहास पुराना है। सवाल कई हैं, लेकिन कांग्रेस क्या आत्ममंथन करेगी, यह सबसे बड़ा प्रश्न है।

बारह वर्षों में सामाजिक न्याय की उल्लेखनीय लड़ाई

नजरिया

प्रो. कन्हैया त्रिपाठी

लेखक राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी रह चुके हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय पंजाब में चेयर प्रोफ़ेसर हैं।

देश में व्याप्त नशाखोरी से भी लड़ना आसान नहीं है। अब भारत नशामुक्ति की ओर निकल पड़ा है। पूरी दुनिया जानती हैं कि भारत की युवा आबादी देश की सबसे बड़ी शक्ति है। विदेशी ड्रग्स ट्रैफिकिंग की समस्या से बचते हुए नशा मुक्त भारत अभियान ने जन-जागरूकता के क्षेत्र में नई मिसाल कायम की है। नशामुक्त भारत अभियान के तहत 26.28 करोड़ से अधिक नागरिकों तक पहुंच बनाई है। इसमें 9.56 करोड़ युवा शामिल हैं। यद्यपि भारतीय नशामुक्ति का इससे दावा तो नहीं होता लेकिन यदि करोड़ों युवा एक-दूसरे का हाथ पकड़कर नशाखोरी से मुक्ति का संकल्प ले रहे हैं तो उम्मीदें बढ़ती हैं। डिजिटल डैशबोर्ड, धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं की भागीदारी तथा सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से नशे के विरुद्ध सामाजिक आंदोलन खड़ा करने का प्रयास अब सफल हो रहा है।

भारत में सामाजिक न्याय की अवधारणा लंबे समय तक सहायता और अनुदान तक सीमित रही, लेकिन पिछले 12 वर्षों में यह दृष्टिकोण व्यापक रूप से बदला है। इस मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार स्वयं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को साकार करने में दृढ़ संकल्प लेकर कार्य कर रहे हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी हालिया समीक्षा यह दर्शाती है कि देश ने कल्याणकारी योजनाओं को अधिकार-आधारित और सशक्तिकरण-केंद्रित मॉडल में बदलने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया है। डिजिटल पारदर्शिता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण-डीबीटी, सामाजिक सुरक्षा और उद्यमिता प्रोत्साहन के माध्यम से 11 करोड़ से अधिक नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। शिक्षा में डिजिटल क्रांति को बढ़ावा मिला। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्रभावी माध्यम है इसके लिए छात्रवृत्ति वितरण प्रणाली में व्यापक सुधार हुए और आधार-लिंक्ड डीबीटी मॉडल लागू किया गया जिससे भ्रष्टाचार, बिचौलियों और भुगतान में देरी जैसी समस्याओं पर प्रभावी अंकुश लगा। अनुसूचित जाति पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत अब तक 6.12 करोड़ छात्रों को 46,581.54 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की जा चुकी है। वहीं प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से 2.99 करोड़ छात्रों को 4,893.03 करोड़ रुपये का लाभ मिला है। पीएम-यशस्वी योजना के तहत ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी समुदायों के 10.69 करोड़ से अधिक छात्र-लाभार्थियों को 15,555.53 करोड़ रुपये की सहायता, छात्रावास सुविधाएं तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराए गए। यह केवल आर्थिक सहायता नहीं बल्कि सामाजिक गतिशीलता का मजबूत आधार है।

देखा जाए तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने सामाजिक न्याय की मजबूती के लिए जो पहल किए वह भी उल्लेखनीय है। हम जानते हैं कि सामाजिक न्याय केवल आर्थिक सहायता से नहीं बल्कि कानूनी सुरक्षा से भी सुनिश्चित होता है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में किए गए संशोधनों, विशेष अदालतों की स्थापना और पीड़ित सहायता तंत्र को मजबूत बनाने से न्यायिक प्रक्रिया अधिक प्रभावी हुई है। वर्ष 2014 से अब तक 7.26 लाख अत्याचार पीड़ितों को 5,012.17 करोड़ रुपये की प्रत्यक्ष सहायता प्रदान की गई है। यह आंकड़ा दर्शाता है कि सरकार ने केवल कानून बनाने तक ही सीमित नहीं रही बल्कि पीड़ितों को वास्तविक राहत भी उपलब्ध कराई।

देश में व्याप्त नशाखोरी से भी लड़ना आसान नहीं है। अब भारत नशामुक्ति की ओर निकल पड़ा है। पूरी दुनिया जानती है कि भारत की युवा आबादी देश की सबसे बड़ी शक्ति है। विदेशी ड्रग्स ट्रैफिकिंग की समस्या से बचते हुए नशा मुक्त भारत अभियान ने जन-जागरूकता के क्षेत्र में नई मिसाल कायम की है। नशामुक्त भारत अभियान के तहत 26.28 करोड़ से अधिक नागरिकों तक पहुंच बनाई है। इसमें 9.56 करोड़ युवा शामिल हैं। यद्यपि भारतीय नशामुक्ति का इससे दावा तो नहीं होता लेकिन यदि करोड़ों युवा एक-दूसरे का हाथ पकड़कर नशाखोरी से मुक्ति का संकल्प ले रहे हैं तो उम्मीदें बढ़ती हैं। डिजिटल डैशबोर्ड, धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं की भागीदारी तथा सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से नशे के विरुद्ध सामाजिक आंदोलन खड़ा करने का प्रयास अब सफल हो रहा है।

नशाखोरी की समस्या से निजात पाने की कोशिश करते भारत में एक सभ्य समाज की पहचान उसके बुजुर्गों के प्रति व्यवहार से होती है, यह समझ विकसित हुई है। अटल-वयो-अभ्युदय योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए देखभाल और सम्मान को संस्थागत स्वरूप देखने को मिल रहा है। अब तक राष्ट्रीय वयोश्री शिविरों के माध्यम से 85 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को 4.63 करोड़ सहायक उपकरण निःशुल्क मिल चुके हैं। वहीं राष्ट्रीय एल्डरलाइन सेवा 14567 ने 29 लाख से अधिक कॉलों का सफल समाधान कर वरिष्ठ नागरिकों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराई है। वयो-सम्मान के साथ ट्रांसजेंडर समुदाय की गरिमा और पहचान के लिए विगत 12 वर्षों में जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने काम किया वह भी उल्लेखनीय लगता है। सरकार ने समझा है कि समावेशी विकास तभी संभव है जब समाज के प्रत्येक वर्ग को समान अवसर मिले। स्माइल योजना के अंतर्गत ट्रांसजेंडर समुदाय को कानूनी पहचान, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।

अब तक 33,189 ट्रांसजेंडर पहचान प्रमाणपत्र जारी हुए। गरिमा गृह आश्रय केंद्रों की स्थापना तथा आयुष्मान भारत योजना में जेंडर-अफर्मेशन प्रक्रियाओं को शामिल करना इस समुदाय की गरिमा बहाली की दिशा में ऐतिहासिक पहल मानी जा रही है। सामाजिक न्याय उद्यमिता और आत्मनिर्भरता के विस्तार तक देखी जा रही है। हम सब जानते हैं कि सामाजिक न्याय का वास्तविक उद्देश्य लाभार्थियों को आत्मनिर्भर बनाना है। अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के लिए वेंचर कैपिटल फंड योजनाओं के माध्यम से 750 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है। इससे हजारों युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। यह पहल लाभार्थियों को सहायता पाने वाले नागरिक से रोजगार सृजक उद्यमी में बदलने का प्रयास है। वहीं स्वच्छता कर्मियों के सम्मान की दिशा में बड़ा कदम कई जगह उठाये गए हैं। निःसंदेह मुझे इस बात का गर्व है कि पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय बठिंडा में डॉ. आंबेडकर चेयर के चेयर प्रोफ़ेसर के रूप में सफाई कर्मचारियों का सम्मान करके सामाजिक न्याय व गरिमा के दिशा में हमने भी सहयोग दिया है। देश के स्वच्छता कर्मियों की सुरक्षा और सम्मान लंबे समय से एक महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दा रहा है। सरकार द्वारा नमस्ते योजना के तहत सीवर सफाई के पूर्ण मशीनीकरण पर जोर दिया गया है ताकि मानव जीवन को जोखिम में डालने वाली मैनुअल सफाई की प्रथा समाप्त हो सके। इस दिशा में 3.42 लाख सफाई कर्मचारियों के लिए 2,383.06 करोड़ रुपये की रियायती वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है। यह पहल केवल तकनीकी सुधार नहीं बल्कि मानव गरिमा की रक्षा का भी महत्वपूर्ण प्रयास है। लेकिन डॉ. आंबेडकर चेयर के माध्यम से जो सम्मान हुआ उसका तो मैं प्रत्यक्षदर्शी व अनुभूति स्वयं मेरे पास है। ऐसे विविध पक्ष जो भारतीय सामाजिक न्याय की इबारत लिखने की पहल भारत में पिछले 12 वर्षों की उपलब्धियों में दर्ज हैं वे संकेत देती हैं कि भारत की सामाजिक न्याय नीति केवल अनुदान आधारित व्यवस्था से आगे बढ़कर अधिकार, गरिमा, सम्मान और अवसर आधारित मॉडल की ओर अग्रसर हुई है। शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, ट्रांसजेंडर अधिकार, वरिष्ठ नागरिक कल्याण, उद्यमिता और स्वच्छता कर्मियों की सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में हुए निवेश ने करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। हालांकि चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने कल्याणकारी योजनाओं को जनसशक्तिकरण के प्रभावी उपकरण में बदलने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। आने वाले वर्षों में इन पहलों की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि लाभार्थियों तक सेवाओं की पहुंच कितनी व्यापक और प्रभावी बनती है। तब ही सरकार के 12 वर्ष के कठिन परिश्रम, ईमानदार व्यवस्था में हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को देश अंकित कर पायेगा और प्राप्त लक्ष्य वास्तविक अर्थों में साकार हो सकेगा।

संयुक्त राष्ट्र के महासचिव गुटेरेस ने 2023 में कहा था कि सामाजिक न्याय के लिए वैश्विक गठबन्धन एक महत्वपूर्ण बल को प्रदर्शित करता है, जिससे टिकाऊ विकास को आगे बढ़ाने और मौजूदा व भावी चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी। यह पहल सामाजिक अनुबन्ध को फिर से तैयार करने पर लक्षित है, जिसे व्यक्ति-आधारित नीतियों से हासिल किया जाएगा और इन प्रयासों में सामाजिक न्याय पर विशेष बल दिया जाएगा। अभी तक दुनिया किस तरह आगे बढ़ी है किसी से छुपा नहीं है लेकिन इस बात का संतोष है कि भारत सरकार ने विगत 12 वर्षों में जो कार्य किया है यदि वह ऐसे ही करती रही तो सामाजिक न्याय की इबारत की दलीलें लोग भारत से दिया करेंगे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति और त्रिभाषा सूत्र का बदलाव

दूरगामी फैसला

प्रो तेजिंदर शर्मा

(कुरुक्षेत्र विवि में प्रोफेसर)

इस फैसले से छात्रों को बहुमुखी फायदे होंगे, जो उनके मानसिक, व्यावसायिक और सामाजिक जीवन को पूरी तरह बदल देंगे। जब एक छात्र एक से अधिक भाषाएं सीखता है, तो केवल उसके शब्दकोश में नए शब्द नहीं जुड़ते, बल्कि उसका पूरा व्यक्तित्व निखर जाता है। सबसे पहला बड़ा फायदा उनके मानसिक विकास में दिखता है; वैज्ञानिकों का मानना है कि बचपन में ही दो या तीन भाषाएं सीख लेने वाले बच्चों का दिमाग ज्यादा लचीला और तेज होता है, जिससे उनकी प्रॉब्लम-सॉल्विंग (समस्या सुलझाने की) क्षमता दूसरों से कहीं बेहतर हो जाती है।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत एक बड़ा और दूरगामी फैसला लिया है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से कक्षा नौवीं के छात्रों के लिए 'त्रि-भाषा फॉर्मूला' लागू होने जा रहा है। इस नए नियम के तहत अब विद्यार्थियों को तीन भाषाएं पढ़नी होंगी, जिनमें से कम से कम दो भारतीय भाषाएं होना अनिवार्य है। इस कदम का सीधा उद्देश्य भारतीय शिक्षा को ज्यादा रोजगारपरक, वैश्विक और साथ ही अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ा हुआ बनाना है। यह फैसला केवल एक नीतिगत बदलाव नहीं है, बल्कि यह हमारे बच्चों के मानसिक विकास और भविष्य की संभावनाओं को एक नई दिशा देने वाला कदम है।

त्रिभाषा फार्मूला की शुरुआत 1964-66 में कोठारी आयोग द्वारा देश की भाषाई विविधता को संजोने और एकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी, जिसे बाद में 1968, 1986 और 1992 की राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों में अपनाया गया। इसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को आगे बढ़ाते हुए, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इसे और अधिक लचीला और सरल रूप दिया गया है। इसके तहत छात्रों को स्कूली शिक्षा के दौरान तीन भाषाएं पढ़नी होंगी, जिनमेंसे कम से कम दो भाषाएं भारतीय होनी अनिवार्य है, जबकि तीसरी भाषा के रूप में छात्र किसी भी भारतीय या विदेशी भाषा का चुनाव अपनी रुचि और सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। इस पूरी व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि सरकार किसी पर भी कोई भाषा थोपने के बजाय छात्रों को अपनी पसंद की भाषाचुनने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करती है। यह भ्रांति कि केवल भारतीय बच्चों पर ही बहुभाषी होने का बोझ है,पूरी तरह निराधार है। वास्तव में, विकसित देशों में भी कई भाषाएं सीखना एक मानक प्रक्रिया है। यूरोप के देशों (जैसे जर्मनी, स्विट्जरलैंड) मेंस्कूली शिक्षा के दौरान मातृभाषा के साथ दो-तीन अन्य भाषाएं सीखना अनिवार्य है। चीन और सिंगापुर जैसे देश अपनी संस्कृति से जुड़े रहने केसाथ-साथ वैश्विक प्रतिस्पर्धा में टिके रहने के लिए 'द्वि-भाषी नीति' कोअपना रहे हैं। यहाँ तक कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे अंग्रेजी भाषी देश भी अब अपनी शिक्षा प्रणाली में स्पैनिश, फ्रेंच और चीनी जैसी विदेशी भाषाओंको शामिल कर रहे हैं, ताकि उनके नागरिक बदलती दुनिया के साथ बेहतर संवाद कर सकें। बहुभाषावाद आज के युग की आवश्यकता है, न कि कोई अतिरिक्त बोझ।

इस फैसले से छात्रों को बहुमुखी फायदे होंगे, जो उनके मानसिक, व्यावसायिक और सामाजिक जीवन को पूरी तरह बदल देंगे। जब एक छात्र एक से अधिक भाषाएं सीखता है, तो केवल उसके शब्दकोश में नए शब्द नहीं जुड़ते,बल्कि उसका पूरा व्यक्तित्व निखर जाता है। सबसे पहला बड़ा फायदा उनके मानसिक विकास में दिखता है; वैज्ञानिकों का मानना है कि बचपन में ही दो या तीन भाषाएं सीख लेने वाले बच्चों का दिमाग ज्यादा

लचीला और तेज होताहै, जिससे उनकी प्रॉब्लम-सॉल्विंग (समस्या सुलझाने की) क्षमता दूसरों से कहीं बेहतर हो जाती है। इसके अलावा, आज की 'ग्लोबल विलेज' बन चुकी दुनिया में यह फैसला करियर और रोजगार के बेहतरीन नए मौके खोलेगा। यदि किसी छात्र को हिंदी और अंग्रेजी के साथ-साथ जापानी या जर्मन जैसी विदेशी भाषाएं आती हैं, तो उसके लिए मल्टीनेशनल कंपनियों में नौकरियों के दरवाजे तुरंत खुलजाते हैं। इन सब के साथ ही, यह कदम देश में सांस्कृतिक एकता को भी मजबूतकरेगा; जब उत्तर भारत का बच्चा तमिल या कन्नड़ सीखेगा, और दक्षिण भारत काबच्चा हिंदी या बंगाली सीखेगा, तो उनके बीच की दूरियां खत्म होंगी क्योंकि भाषाएं केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि दिलों को जोड़ने का एकमजबूत पुल बनती हैं। इस नीति को सफलतापूर्वक लागू करने की राह में कुछ बड़ी चुनौतियाँ भी हैं, जिन पर समय रहते ध्यान देना बेहद जरूरी है। क्योंकि, कोई भी अच्छी नीति तब तक जमीन पर कामयाब नहीं हो सकती जब तक उसकी व्यावहारिक दिक्कतोंको दूर न किया जाए। सीबीएसई के सामने इस फॉर्मूले को लागू करने में सबसे पहली और बड़ी चुनौती शिक्षकों की भारी कमी है, क्योंकि देश में अभी भी भारतीय और विदेशी भाषाओं के योग्य शिक्षकों की बहुत कमी है; अगर स्कूल में जर्मन या तमिल पढ़ाने के लिए टीचर ही नहीं होगा, तो छात्र चाहकर भी उसे नहीं चुन पाएंगे। दूसरी बड़ी समस्या किताबों की उपलब्धता को लेकर है, क्योंकि नए पाठ्यक्रम के अनुसार कक्षा नौवीं के लिए तीनों भाषाओं कीकिताबें समय पर उपलब्ध कराना एक बहुत बड़ा टास्क है। इन सब के साथ ही, इस फैसले से छात्रों पर मानसिक दबाव बढ़ने का भी खतरा है; चूंकि कक्षा नौवीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी का शुरुआती चरण होती है, इसलिए अचानक एक नई भाषा का जुड़ना बच्चों पर पढ़ाई का बोझ बढ़ा सकता है, खासकर उन बच्चों के लिए जोपढ़ाई में थोड़े कमजोर हैं। इस बेहतरीन नीति को कागजों से निकालकर हकीकत में बदलने और बच्चों के भविष्य को सचमुच 'शानदार' बनाने के लिए हमें कुछ लीक से हटकर कदम उठाने होंगे। सबसे पहले, भाषा सीखने में 'रटने' की जगह 'बोलने' पर जोर दियाजाना चाहिए, जिसके तहत तीसरी भाषा को इतिहास या भूगोल की तरह रटकर पास होने वाला विषय बनाने के बजाय कोई भारी-भरकम लिखित परीक्षा न ली जाए और'आंतरिक मूल्यांकन' अपनाया जाए। बच्चों को फिल्में दिखाकर, गाने सुनाकर और आपस में बातचीत के जरिए खेल-खेल में भाषा सिखाई जानी चाहिए। चूंकि, हरस्कूल में तुरंत योग्य टीचर पहुंचाना मुमकिन नहीं है, इसलिए डिजिटल टूल्सऔर ऐप्स का इस्तेमाल करते हुए सरकार और सीबीएसई को 'डुओलिंगो' की तर्जपर अपना एक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहिए, ताकि स्मार्ट क्लास केजरिए देश के किसी भी कोने का बच्चा ऑनलाइन बेस्ट टीचर से कोई भी भाषा सीखसके। इसके साथ ही, विदेशी भाषाओं में 'अंग्रेजी' को लेकर स्पष्टता होना बेहद जरूरी है क्योंकि अंग्रेजी को विदेशी भाषा की श्रेणी में रखने से असमंजस की स्थिति बन सकती है, इसलिए सुझाव यह है कि अंग्रेजी को एक 'अनिवार्य वैश्विक संपर्क भाषा' माना जाए और तीसरी भाषा के रूप में छात्रों को विशुद्ध रूप से किसी एक नई विदेशी भाषा (जैसे फ्रेंच, जर्मन) या किसी अन्य भारतीय भाषा को चुनने का आसान विकल्प दिया जाए। शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए स्कूलों को अंतरिम रूप से सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों या स्थानीय भाषाई विशेषज्ञों की पार्ट-टाइम/ऑनलाइन सेवाएं लेनी चाहिए। साथ ही, शैक्षणिक सत्र 2026-27 से नई भाषा नीति के शुरुआती वर्षों में 'नो-फेल' पॉलिसी (अनुत्तीर्ण न करने की नीति) या केवल ग्रेडिंग सिस्टम लागू किया जाना चाहिए, ताकि छात्रों में परीक्षा का दबाव न रहे और वे स्वाभाविक रूप से नई भाषा सीखने के लिए प्रेरित हों। सीबीएसई का त्रिभाषा फार्मूला देश के स्कूली ढांचे को आधुनिक और वैश्विक बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। यह नीति हमारे बच्चों को एक हाथ में अपनी संस्कृति की किताब और दूसरे हाथ में वैश्विक अवसरों का पासपोर्ट थमाती है। दुनिया के सफल देशों के अनुभवों से सीखते हुए और ऊपर दिए गए व्यावहारिक सुझावों को अपनाकर हम इस नीति को बेहद सफल बना सकते हैं। जरूरत बस इस बात की है कि हम इसे बच्चों पर एक 'विषय का बोझ' न बनने दें, बल्कि इसे 'खिड़की' की तरह पेश करें, जिससे वे बाहर की पूरी दुनिया को एक नए नजरिए से देख सकें। जब भाषा का यह बंधन खुलेगा, तभी तो हमारे देश का युवा वैश्विक मंच पर शान से उड़ेगा।

कॉमेडी, फूहड़ता और स्त्री का बाज़ारीकरण : असली चिंता कहाँ है?

मुद्दा

मालिनी गौतम

लेखक साहित्यकार हैं।

प्रणीत मोरे के शो में वायरल हुए '370 रुपये की बिरयानी' प्रसंग पर बहुत कुछ कहा जा चुका है। संबंधित युवक और कॉमेडियन दोनों ने सफाई दी, आलोचना हुई, माफ़ी भी माँगी गई। लेकिन मुझे लगता है कि यह विवाद किसी एक व्यक्ति या एक वीडियो का नहीं बल्कि उस व्यापक सांस्कृतिक प्रवृत्ति का संकेत है जो लगातार हमारे मनोरंजन जगत में जगह बनाती जा रही है।

सवाल यह नहीं है कि किसी मज़ाक से किसकी भावना आहत हुई। सवाल यह है कि हम किस बात पर हँस रहे हैं। यदि किसी स्त्री के शरीर, उसके वस्त्र, उसकी सहमति या उसके साथ संबंधों को 'निवेश' और 'वसूली' की भाषा में बदल दिया जाए और उस पर सभागार ठहाकों से गूँज उठे तो चिंता का विषय केवल मंच पर खड़ा व्यक्ति नहीं बल्कि वह सामूहिक मानसिकता भी है जो इस हास्य को स्वीकार कर रही है।

यहाँ एक सावधानी भी आवश्यक है। हर तीखा..साहसी या असुविधाजनक मज़ाक अश्लील नहीं होता। अच्छी कॉमेडी सत्ता, समाज, पाखंड और मानवीय कमजोरियों पर चोट करती है। लेकिन जब हास्य का सबसे आसान साधन स्त्री-देह, यौन संकेत और अपमानजनक वस्तुकरण बन जाए, तब वह रचनात्मकता नहीं कल्पनाशक्ति की गरीबी का संकेत अधिक लगता है।

दुर्भाग्य से यह प्रवृत्ति केवल पुरुष कॉमेडियनों तक सीमित नहीं है। हाल के वर्षों में कई महिला स्टैंड-अप कलाकारों के मंचों पर भी यौनिक अनुभवों, शरीर और संबंधों के नाम पर ऐसी फूहड़ता दिखाई देती है जहाँ विचार की जगह सनसनी और सहज हँसी की जगह चौंकाने का प्रयास प्रमुख हो जाता है। इसलिए इसे स्त्री बनाम पुरुष का प्रश्न भर मानना भी पर्याप्त नहीं होगा। समस्या उस मनोरंजन संस्कृति की है जो मानती है कि अश्लीलता, अपमान और उत्तेजना ही सबसे जल्दी बिकने वाला कंटेंट है।

इस पूरे परिदृश्य में तकनीक और बाज़ार की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। पहले ऐसी बातें सीमित समूहों में कही-सुनी जाती थीं। आज एल्गोरिद्म उन्हें लाखों लोगों तक पहुँचाता है। जो सामग्री अधिक उत्तेजक, विवादास्पद और सनसनीखेज़ होती है उसे अधिक व्यूज़ मिलते हैं। परिणामस्वरूप ठहाके भी सार्वजनिक हो गए हैं और उनका व्यापार भी।

विडंबना यह है कि हम अक्सर मान लेते हैं कि स्त्रियों की आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता बढ़ने के साथ उनका सम्मान भी स्वतः बढ़ रहा होगा। जबकि समानांतर रूप से डिजिटल संस्कृति ने उनके शरीर, निजी जीवन और छवि को पहले से कहीं अधिक उपभोग की वस्तु बना दिया है। बाज़ार स्त्री को सशक्त भी करता है और कई बार उसी क्षण उसे उत्पाद में भी बदल देता है। इसलिए बहस का केंद्र किसी एक कॉमेडियन को खलनायक घोषित करना नहीं होना चाहिए। प्रश्न यह होना चाहिए कि क्या हम मनोरंजन के नाम पर स्त्री-विरोधी दृष्टियों को सामान्य बना रहे हैं? क्या हम हास्य और फूहड़ता के बीच का अंतर खोते जा रहे हैं? और क्या हम ऐसी पीढ़ी तैयार कर रहे हैं जो संवेदनशीलता की जगह अपमान को मनोरंजन समझने लगे?

कॉमेडी पर प्रतिबंध समाधान नहीं है। लेकिन कॉमेडी की आलोचना भी उतनी ही वैध है जितनी उसकी स्वतंत्रता। दर्शकों का विवेक, कलाकार की जिम्मेदारी और समाज की संवेदनशीलता तीनों साथ रहेंगे तभी हास्य संस्कृति स्वस्थ रह सकेगी। अन्यथा हर अगला विवाद पिछली सीमा को थोड़ा और आगे धकेल देगा और हम यह सोचते रह जाएँगे कि आखिर हँसी कब विचार से अलग होकर केवल बाज़ार का उत्पाद बन गई।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
वरिष्ठ संपादक
पंकज शुक्ला
प्रबंध संपादक
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

मच्छर को ही मारना आसान नहीं रहा फिर वो तो देश है

व्यंग्य

सुरेश रायकवार

लेखक व्यंग्यकार हैं।

दयारामजी के पोता-पोती सत्यम व साक्षी बोले - दादाजी! बचपन में तो आपने हमें राजा-रानी, चोर-सिपाही, बंदर-भालू की कहानियाँ खूब सुनाई, आज आपसे कोई नई कहानी सुनने की इच्छा है। ठीक है बच्चों! तो आज मैं तुम्हें मच्छर-मच्छरणी की एक बिल्कुल नई कहानी सुनाता हूँ, सुनो - यह कथा है आज से 150 वर्ष पहले की जब फ्रांस के एक शहर में दो पहलवानों के बीच हुई कुश्ती में, एक पहलवान ने एक मच्छर को मसला और दूसरे पहलवान को ललकारते हुए बोला कि मुझसे पंगा मत लेना, नहीं तो मच्छर के जैसा मसल दूंगा। मच्छरणी ने देखा कि पहलवान ने उसके मच्छर को बिना किसी कसूर ही मसल कर मार डाला। यह देखकर उस एनाफ़्लाइज प्रजाति की मच्छरणी ने उसी समय प्रण लिया कि जैसे नागिन अपने नाग का बदला लेती है वह भी मानव जाति से अपने मच्छर का बदला लेकर ही रहेगी। इसके बाद मच्छरणी ने अपनी गैंग की साथिनों के साथ मिलकर वहाँ के तमाम अत्याचारी पूंजीपतियों, जमाखोर, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, व्यभिचारी, चोर-डकैत-लफंगे, बेईमान, शातिर और झूठे नेता, भ्रष्ट-अधिकारी, हत्यारे, नशेड़ी आदि अपराधी-वृत्ति के छंटे हुए लोगों का खून चूस-चूस कर अपने उदर में एकत्र किया। मच्छरणियों के पेट में एकत्रित विभिन्न अत्याचारियों का यह खून, अब एक खतरनाक जहर बन चुका था। इसके बाद मच्छरणियों की इस गैंग ने उस पहलवान सहित शहर के अन्य कई लोगो के शरीर में अपने डंक के माध्यम से इस जहर को प्लांट कर दिया। धीरे-धीरे पूरे शहर में लोग बुखार से परेशान होने लगे। शहर के चारों ओर हाहाकार मचने लगा, मानव को इस तरह परेशान देख मच्छरणी वैसे ही प्रसन्न हुई जैसे बाहुबलियों के सहारे चुनाव जीतने पर कोई पार्टी का नेता।

लगभग चार-पाँच वर्ष लोग इस बुखार से अत्यधिक परेशान रहे, अंततः सन 1880 में फ्रांस ने मलेरिया परजीवी की खोज कर ली। मलेरिया की खोज भले ही कर ली गई किन्तु एनाफ़्लाइज मच्छरणी का, मानव से बदला लेने का सिलसिला पीढ़ी-दर-पीढ़ी अब भी चला आ रहा है, उसमे कमी के स्थान पर बढ़ोतरी ही दिखाई देती है, फ्रांस के उस शहर से निकल कर इनकी प्रजाति ने पूरी दुनिया के मानव को अपना निशाना बना लिया। एनाफ़्लाइज प्रजाति की मच्छरणियों ने जो बच्चे पैदा किए वो भी आतंकवादी ही पैदा किए और उनके नाम रखे है, डेंगू और चिकनगुनिया जो मलेरिया से भी खतरनाक हैं। पहले तो ये गंदे पानी में ही पैदा होते थे किन्तु आजकल इतने एडवांस हो गए है कि साफ पानी में भी पैदा हो जाते हैं।

आधुनिक प्रजाति के मच्छर इतने शातिर हो गए हैं कि कभी-कभी इन मच्छरों को मारने के चक्कर में आदमी स्वयं को थप्पड़ मार लेता है किन्तु मच्छर नहीं मार पाता है। सन 2022 में रूस ने यूक्रेन को और अभी फरवरी 2026 में अमेरिका और इजराइयल के महामानवों ने सोचा कि ईरान को मच्छर जैसा मसल देंगे, किन्तु अब युद्ध में उतरकर इनके पसीने छूट रहे हैं। इन्हे कौन समझाये कि आजकल मच्छर को ही मसलना या मारना आसान नहीं रहा तो ये तो स्वतंत्र देश हैं।

इस एनाफ्लाइज मच्छरणी के काटे का ऐसा प्रभाव है कि आदमी एक सप्ताह तक तो 103-104 डिग्री बुखार में ही तपता रहता है और यदि नहीं संभल पाया तो उसके दिमाग तक में मलेरिया फैला देती है। नाग-नागिन का जहर तो मंत्र से, दवाइयों से उतर भी जाता है किन्तु इन मच्छरणी रानी के जहर के मंत्र अभी तक नहीं बन पाये हैं, ना ही कोई वेक्सिन बन पाई।

मच्छरों से बचाव के लिए देश में प्रतिवर्ष भारी-भरकम राशि के बजट प्रावधान होते है, बजट की राशि तो नेताओं और कर्मचारियों की जेबों में गायब हो जाती हैं किन्तु मच्छर-मच्छरणी मंहगाई की तरह प्रतिवर्ष बढ़ते ही जाते हैं। जैसे सड़क निर्माण, पुल निर्माण, बांध निर्माण, टीकाकरण आदि सरकारी कार्यों में भ्रष्टाचार सहजसाध्य होता है वैसे ही, कहते हैं मलेरिया विभाग में भी बहुत स्कोप है।

सरकारें अपने देश की महान विभूतियों के दिवस भले ही ना मनाए किन्तु 25 अप्रेल को मलेरिया दिवस और 20 अगस्त को मच्छर दिवस अवश्य मनाती है। मच्छरों को भगाने के लिए ये सरकारें कई कदम उठाती हैं, जैसे शहरों कि गलियों में धुआँ उड़वाती हैं, दवाइयों का छिडकाव करवाती हैं, जागरूकता के विशेष अभियान चलाती है आदि।

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मच्छर और मानव एक ही राशी के होते हैं। आदमी कहीं रिश्वत लेकर खून चूसता है तो कहीं घोटाले करके। मालिक नौकरों का, तो धनवान गरीबों का खून चूसता हैं। डॉक्टर मोटी-मोटी फीस लेकर, तो दवाई वाले नाममात्र की लागत वाली दवाइयों के हजारों गुना दाम वसूल कर या नकली दवाइयाँ खिलाकर मरीजों का खून चूस रहें है। किन्तु मच्छर इस मामले में कोई भेदभाव नहीं करते है वे खून चूसते समय यह नहीं देखते कि कौन अमीर है कौन गरीब है, कौन हिन्दू है कौन मुस्लिम है, जहां मौका मिल जाए उसीका खून चूस लेते है आखिर सबके खून का रंग और स्वाद एक-सा ही तो होता है।

विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर विशेष

अतुल गोयल

लेखक न्यूयॉर्क की कंपनी में सॉफ्टवेयर डवलपमेंट इंजीनियर हैं।

बचपन को लौटाना होगा उसका खोया आसमान

दुनियाभर में लगभग 16 करोड़ बच्चे बाल श्रमिक हैं, जिनमें से लगभग 8 करोड़ बच्चे खतरनाक श्रम कार्यों में लगे हुए हैं। यह आंकड़ा दर्शाता है कि हर 10 में से एक बच्चा अपने बचपन के बजाय किसी मजदूरी की जगह पर खड़ा है। इन 16 करोड़ बच्चों में से एशिया और प्रशांत क्षेत्र में लगभग 4.9 करोड़, अफ्रीका में लगभग 8.6 करोड़, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन में 1.1 करोड़ बच्चे इस समस्या से पीड़ित हैं। इस समय सर्वाधिक गंभीर स्थिति उप-सहारा अफ्रीका की है, जहां प्रत्येक दसवां बच्चा श्रमिक है। भारत की स्थिति भी चिंताजनक है। भारत में 5 से 14 वर्ष की आयु के लगभग 1.01 करोड़ बच्चे बाल श्रमिक हैं। हालांकि पिछले दो दशकों में शिक्षा के प्रचार, सरकारी योजनाओं और गैर-सरकारी संगठनों की मेहनत से बाल श्रमिकों की संख्या में गिरावट आई है लेकिन शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्योगों, घरेलू कामों और खेती-बाड़ी जैसे असंगठित क्षेत्रों में इनकी उपस्थिति अब भी भारी है।

हर वर्ष 12 जून को 'विश्व बाल श्रम निषेध दिवस' मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2002 में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) ने बच्चों को मजदूरी से मुक्त कराने और उनके बचपन को सुरक्षित करने के उद्देश्य से की थी। वर्ष 2026 में इस दिवस की थीम है 'बाल श्रम के खिलाफ लाल कार्ड: बच्चों के लिए निष्पक्ष खेल, व्यस्कों के लिए सम्मानजनक काम'। बाल श्रम बच्चों के मौलिक अधिकारों के साथ ही उनके जीवन की संभावनाओं को भी निगल रहा है। छोटे-छोटे ढाबों, चाय की दुकानों, ईंट भट्टों, कालीन बुनाई केंद्रों, बीड़ी, कांच, पटाखा और चूड़ी उद्योगों में काम करते मासूम बच्चों को देखना एक आम दृश्य है। बाल श्रम कोई सरल या सतही समस्या नहीं है। यह उस गंभीर सामाजिक विडंबना का परिणाम है, जिसमें समाज, सरकार, उद्योग और व्यक्तिगत स्वार्थ की जटिलताएं आपस में उलझी हुई हैं। किसी भी बच्चे को उसकी इच्छा के विरुद्ध काम पर लगाना, उसे शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल जैसी मूलभूत चीजों से दूर करना, सीधा-सीधा उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

दुनियाभर में लगभग 16 करोड़ बच्चे बाल श्रमिक हैं, जिनमें से लगभग 8 करोड़ बच्चे खतरनाक श्रम कार्यों में लगे हुए हैं। यह आंकड़ा दर्शाता है कि हर 10 में से एक बच्चा अपने बचपन के बजाय किसी मजदूरी की जगह पर खड़ा है। इन 16 करोड़ बच्चों में से एशिया और प्रशांत क्षेत्र में लगभग 4.9 करोड़, अफ्रीका में लगभग 8.6 करोड़, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन में 1.1 करोड़ बच्चे इस समस्या से पीड़ित हैं। इस समय सर्वाधिक गंभीर स्थिति उप-सहारा अफ्रीका की है, जहां प्रत्येक दसवां बच्चा श्रमिक है। भारत की स्थिति भी चिंताजनक है। भारत में 5 से 14 वर्ष की आयु के लगभग 1.01 करोड़ बच्चे बाल श्रमिक हैं। हालांकि पिछले दो दशकों में शिक्षा के प्रचार, सरकारी योजनाओं और गैर-सरकारी संगठनों की मेहनत से बाल श्रमिकों की संख्या में गिरावट आई है लेकिन शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्योगों, घरेलू कामों और खेती-बाड़ी जैसे असंगठित क्षेत्रों में इनकी उपस्थिति अब भी भारी है। महामारी के बाद की परिस्थितियों में बाल श्रम का पुनरुत्थान देखने को मिला है। कोविड-19 के कारण परिवारों की आर्थिक स्थिति खराब होने से कई बच्चों को पढ़ाई छोड़कर काम पर जाना पड़ा। भारत के कई हिस्सों में बच्चों को आज भी पढ़ाई और खेल के बजाय दिनभर मजदूरी में झोंक दिया जाता है। कभी वे सड़क किनारे भीख मांगते, कचरा बीनते, जूते पॉलिश करते या कारखानों में सस्ते श्रमिक की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। बाल श्रम बच्चों को न केवल शिक्षा के अधिकार से वंचित करता है बल्कि उन्हें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्तर पर भी हानि पहुंचाता है। अस्वच्छ और खतरनाक वातावरण में काम करने के कारण बच्चों को सांस की बीमारी, अस्थमा, त्वचा रोग, टीबी, रीढ़ की हड्डी के विकार और कैंसर तक हो सकता है। साथ ही लंबे समय तक पोषण की कमी और शारीरिक शोषण के कारण वे उम्र से पहले बूढ़े दिखने लगते हैं और मानसिक रूप से भी अवसाद, डर, हीनता ग्रंथि और अपराध की दुनिया की ओर प्रवृत्त हो सकते हैं। यह समस्या सिर्फ मानवीय संकट नहीं है, यह आर्थिक और सामाजिक विकास में भी बाधा है। एक समाज का भविष्य उसकी युवा पीढ़ी पर निर्भर करता है। यदि वह पीढ़ी शिक्षा के बजाय बचपन में ही मजदूरी करने लग जाए तो न केवल उसका जीवन अंधकारमय हो जाता है बल्कि पूरे राष्ट्र की प्रगति भी अवरुद्ध हो जाती है। मानव संसाधन की क्षति, उत्पादकता में गिरावट और सामाजिक असमानता जैसे दुष्परिणाम सामने आते हैं।

बाल श्रम के पीछे अनेक कारण हैं लेकिन गरीबी इसकी सबसे मजबूत जड़ है। जब एक परिवार अपनी बुनियादी आवश्यकताओं भोजन, पानी, दवा और शिक्षा को पूरा नहीं कर पाता तो बच्चे को स्कूल भेजने के बजाय काम पर भेज देना मजबूरी बन जाती है। इसके अलावा निरक्षरता, कुपोषण, किसी सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच का अभाव, बाल तस्करी और अज्ञानता भी बाल श्रम के प्रमुख कारक हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अभिभावकों को यह तक पता नहीं होता कि उनके बच्चे को मजदूरी पर लगाना कानूनी अपराध है और संविधान उनके बच्चे को

शिक्षा और सुरक्षित बचपन का अधिकार देता है। बाल श्रम को रोकने के लिए भारत में 'बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम 1986' बनाया गया था, जिसे 2016 में संशोधित कर और कठोर किया गया। इस संशोधन में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के किसी भी कार्य में नियोजन पर पूर्ण प्रतिबंध है, साथ ही 14-18 वर्ष के किशोरों को खतरनाक उद्योगों में काम पर लगाने पर भी रोक लगाई गई है। इसके बावजूद इस कानून की प्रभावशीलता संदिग्ध बनी हुई है क्योंकि निगरानी, प्रवर्तन और सजा की प्रक्रियाएं अपेक्षाकृत कमजोर हैं। कई बार बच्चा 'परिवार की मदद' के नाम पर घरेलू उद्योगों में कार्य करता रहता है और कानून इसकी सही से व्याख्या नहीं कर पाता। बाल श्रम से जुड़ी एक बड़ी विडंबना यह भी है कि कई बार इन्हें बचाने वाले कानून ही इनके अधिकारों की राह में बाधा बन जाते हैं। उदाहरण के तौर पर जब कानून में यह प्रावधान है कि बच्चा पारिवारिक काम कर सकता है तो इसका फायदा उठाकर बाल मजदूरी को पारिवारिक रोजगार बताकर उसे वैध ठहराने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा असंगठित क्षेत्रों में, जहां निरीक्षण की व्यवस्था नहीं है, वहां तो स्थिति और भी भयावह होती है। भारत सरकार ने 'राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना' जैसी योजनाएं भी चलाई हैं, जिनका उद्देश्य 9 से 14 वर्ष की आयु के बाल श्रमिकों को बचाकर उन्हें विशेष विद्यालयों में दाखिल कराना और उन्हें पुनर्वास सहायता देना है लेकिन इन योजनाओं का कार्यान्वयन और जमीनी असर आज भी सीमित और असमान है। कई जिलों में इनकी उपस्थिति नहीं है और जहां है भी, वहां संसाधनों और प्रशिक्षित मानवबल की कमी है। यदि भारत को सच में बाल श्रम मुक्त बनाना है तो केवल कानून बनाना या कुछ योजनाएं शुरू करना पर्याप्त नहीं होगा। इसके लिए व्यापक सामाजिक बदलाव की आवश्यकता है। सबसे पहले तो सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण जैसे मूलभूत क्षेत्रों में निवेश बढ़ाना होगा ताकि गरीब परिवार अपने बच्चों को स्कूल भेजने में सक्षम बनें। साथ ही कौशल विकास कार्यक्रमों को मजबूत बनाकर युवाओं को रोजगार योग्य बनाना होगा ताकि गरीबी का दुष्चक्र टूट सके। दूसरी ओर, समाज को भी बाल श्रम के खिलाफ एकजुट होना होगा। जब तक हम अपने आस-पास किसी ढाबे या कारखाने में बच्चों को काम करते देखते हुए चुप रहते हैं, तब तक इस समस्या का हल नहीं निकल सकता।

स्कूल, पंचायत, युवा क्लब, महिला संगठन, सब मिलकर बाल श्रम के खिलाफ सामूहिक प्रयास करें, तभी बात बनेगी। प्रौद्योगिकी के इस युग में आवश्यक हो गया है कि डिजिटल माध्यमों का उपयोग करके बच्चों के अधिकारों की रक्षा की जाए। सोशल मीडिया और मोबाइल एप्स के जरिये भी बाल श्रम की घटनाओं की रिपोर्टिंग को सुलभ और प्रभावशाली बनाया जा सकता है। इसके अलावा, बच्चों को सशक्त बनाने के लिए उन्हें उनके अधिकारों की जानकारी देना और सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत लाना बेहद जरूरी है। बाल श्रम केवल एक सामाजिक या कानूनी समस्या नहीं है, यह मानवता के खिलाफ अपराध है। जब तक एक भी बच्चा स्कूल के बजाय मजदूरी कर रहा है, तब तक हम एक सभ्य समाज कहलाने के अधिकारी नहीं हैं। जिस दिन हर बच्चा पढ़ाई, खेल और स्वप्न देखने की आजादी महसूस करेगा, वही दिन होगा, जब भारत वास्तव में 'नया भारत' कहलाने योग्य बनेगा। हमें उस दिशा में आज ही, अभी से, पूरी ताकत और नीयत के साथ चलना होगा। यही हमारे बच्चों के प्रति सच्चा कर्तव्य और भविष्य के भारत के प्रति हमारी जिम्मेदारी है।

विश्व बाल निषेध दिवस

डॉ. रमेश ठाकुर

'बालश्रम' समाप्ति के लिए वैश्विक मंथन की दरकार

कानून और संविधान में प्रत्येक बच्चे को शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान सहित गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार सुनिश्चित है। बावजूद इसके गरीब, अक्षम और असहाय बच्चों के साथ असमानता और भेदभाव किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद-24 के मुताबिक किसी भी कर-कारखानों में 14 वर्ष सेकम उम्र के बच्चों के रोजगार पर पूर्ण प्रतिबंध होने के बाद भी चोरी-छिपे बच्चों से काम करवाया जाता है। ये बात शासन से लेकर स्थानीय प्रशासन केलोग भी भली-भांति जानते हैं। लेकिन कार्रवाई के जगह अपनी आंख मूंदे रहते हैं। जबकि, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार ने साल-1986 में बाल श्रम के विरूद्ध रोकथाम के लिए कठोर अधिनियम बनाया था जिसके तहत बच्चों को खतरनाक जगहों जैसे खादानों, मशीनरी कारखानों में जबरन काम करवानेवालों पर दंडनीय अपराध का प्रावधान तय किया था। लेकिन इस कठोर कानून कीभी खुलआम धज्जियां उड़ाई जाती हैं।

सदस्य, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान, भारत सरकार 'बालश्रम' समस्या दशकों से न सिर्फ भारत में, बल्कि समूचे संसार में प्रचलित रही है। वैसे, बालश्रम अपने आप में किसी कलंक से कम नहीं? भारत की बात करें, तो लाखों की संख्या में नौनिहाल विभिन्न राज्यों में किसी न किसी मजबूरी के चलते अपने जीवन को श्रम की भट्टियों में झुका हुआ है। हालांकि, सरकारी और सामाजिक स्तर पर रोकने की कोशिशों में कोई कोर-कसर नहीं? पर, समस्या घटने के जगह बढ़ ही रही है दिनोंदिन। आज 'विश्व बाल श्रम निषेध दिवस' है जो सालाना 12 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरूआत वर्ष-2002 में 'अंनराष्ट्रीय श्रम संगठन' की अगुआई में बड़े वैचारिक स्तर पर मुकर्रर की गई थी। दिवस का आज 24वीं संस्करण पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। मकसद, चाइल्ड लेबर के विरूद्ध वैश्विक मंचों पर ईमानदारी से जागरूकता फैलाना और बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने को लेकर जनमानस को आहवान करना।

कानून और संविधान में प्रत्येक बच्चे को शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान सहित गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार सुनिश्चित है। बावजूद इसके गरीब, अक्षम और असहाय बच्चों के साथ असमानता और भेदभाव किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद-24 के मुताबिक किसी भी कर-कारखानों में 14 वर्ष सेकम उम्र के बच्चों के रोजगार पर पूर्ण प्रतिबंध होने के बाद भी चोरी-छिपे बच्चों से काम करवाया जाता है। ये बात शासन से लेकर स्थानीय प्रशासन केलोग भी भली भांति जानते हैं। लेकिन कार्रवाई के जगह अपनी आंख मूंदे रहते हैं। जबकि, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार ने साल-1986 में बाल श्रम के विरूद्ध रोकथाम के लिए कठोर अधिनियम बनाया था जिसके तहत बच्चों को खतरनाक जगहों जैसे खादानों, मशीनरी कारखानों में जबरन काम करवाने वालों पर दंडनीय अपराध का प्रावधान तय किया था। लेकिन इस कठोर कानून कीभी खुलआम धज्जियां उड़ाई जाती हैं।

दरअसल, बाल श्रम ऐसा अभिशाप है जो किसी भी विकसित मुल्क की प्रगति में घोर बाधक रूपी असर छोड़ता है। बीते वर्ष 'विश्व बाल श्रम निषेध दिवस'-2025 की थीम थी 'प्रगति स्पष्ट है, लेकिन अभी और काम करना बाकी है'। वहीं, इसवर्ष यानी 2026 की थीम है 'बाल श्रम को लाल कार्ड-बच्चों के लिए उचित खेल, वयस्कों के लिए सम्मानजनक काम' रखी गई है। गंभीरता से अगर विमर्श करें, तो ये दिवस तभी सफलता अर्जित कर पाएगा। जब सभी एकजुट होकर इस बुराई से लड़ेंगे। संकल्प लें कि बाल श्रम के खिलाफ समाज में जागरूकता फैलाएंगे और मासूमों के बचपन के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। बच्चे देश का भविष्यहैं। हम सबका दायित्व है कि इन्हें बेहतर 'आज' दें ताकि सुनहरे 'कल' का निर्माण कर सकें।

बालश्रम के विश्वस्तरीय आंकड़े रोंगटे खड़े करते हैं। बाल अधिकार रक्षक संस्थाओं और उनके विशेषज्ञों के अनुसार करीब 1 करोड़ 1 लाख बच्चे पूरे भारत में बाल श्रम में शामिल हैं जिनमें 56 लाख लड़के और 45 लाख लड़किया,जिनकी उम्र 5 से 14 के बीच है। ये बच्चे बीड़ी बनाना, सूत काटना, होटल-ढाबों में चाकरी करना, कृषि कार्यों, कालीन बुनाई व घरेलू कार्योंमें ज्यादा लगे हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश में बाल श्रमिकों की सर्वाधिक संख्या को सरकार की अधिकृत बाल समितियों द्वारा बताई है। वहीं, पूरे विश्व में बाल श्रमिकों की बातकरें, तो 'अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन' और 'यूनिसेफ' की रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया के 198 देशों में इस समय 13 करोड़ 80 लाख से अधिक बच्चे इस वक्त चाइल्ड लेबर में संलिप्त हैं। यानी प्रत्येक 10वें बच्चे पर एक बच्चा बाल मजदूरी कर रहा है। इस कलंक को जड़ से खत्म करने के लिए एक और वैश्विक मंच सजाने की जरूरत है जहां इस मसले पर विमर्श करके पूर्व समाधानका कोई मुकम्मल रास्ता निकाला जा सके।

जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 5-11 वर्ष आयु वर्ग की कुल बाल जनसंख्या 259.6 मिलियन थी जिसमें 10 मिलियन से अधिक यानी 4 फीसदी आबादी बाल श्रमिकों की पाई गई थी। आज 2026 में 146 करोड़ आबादी में इन आंकड़ों परगौरफरमाते हैं तो ये आंकड़े काफी बढ़े दिखाई देते हैं। बाल अपराध, बालश्रमिकों की संख्या में इजाफा बीते कुछ दशकों में तेजी से बढ़ा है। भारतमें सालाना करीब 2.3 से 2.5 करोड़ बच्चे पैदा होते हैं। हर दिन औसतन 63 हजार से 73 हजार बच्चे जन्म लेते हैं जिसमें गरीब और अल्पसंख्यकों कीसंख्या सर्वाधिक है। हालांकि, 'हम दो, हमारे दो' के स्लोगन के बाद शिक्षित वर्ग में जनसंख्या नियंत्रण भाग पनपा है। बाल श्रम कलंक को मिटाने के लिए सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा पर ज्यादा जोर देना होगा। शिक्षा के अधिकार की अलख शहरों के मुकाबले कस्बों-गांवों में ज्यादा फैलाने की दरकार है। केंद्र व राज्यों सरकारों को नई नीति बनानी होगी जिसमें शुरुआती शिक्षा से कोई बच्चा वंचित न रह सके। ऐसा करने के बाद ही बाल श्रम जैसे अभिशाप से मुक्ति पाने की कल्पना की जा सकेगी।

सायबर सुरक्षा

ममता कुशवाहा

लेखक शिक्षक हैं।

इंटरनेट के युग में बचपन की रक्षा का दायित्व

कुछ समय पहले भारत में एक चर्चित घटना सामने आई, जब एक ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म पर बच्चों के व्यक्तिगत डेटा के दुरुपयोग और अनुचितविज्ञापनों को लेकर गंभीर प्रश्न उठे। इसी प्रकार कई स्कूलों में उपयोगहोने वाले शैक्षणिक ऐप्स पर यह आरोप लगा कि वे बच्चों की गतिविधियों, व्यवहार और पसंद-नापसंद से जुड़ी सूचनाएँ एकत्र कर रहे हैं। इन घटनाओं ने एक बार फिर यह प्रश्न हमारे सामने खड़ा कर दिया कि जिस डिजिटल संसार को हम बच्चों के उज्ज्वल भविष्य का माध्यम मान रहे हैं, क्या वह वास्तव में उनके लिए सुरक्षित भी है? आज जब स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेमिंग और डिजिटल शिक्षा बच्चों के दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं, तब डिजिटल युग में बच्चों की सुरक्षा केवल तकनीकी विषय नहीं रह गई है, बल्कि यह सामाजिक, नैतिक, कानूनी और शैक्षिक चिंता का विषय बन चुकी है।

इक्कीसवीं सदी के इस डिजिटल युग में बच्चों का इंटरनेट से परिचय बहुत कम आयु में ही हो जाता है। कोविड-19 महामारी के दौरान ऑनलाइन शिक्षा ने इस प्रक्रिया को और तेज कर दिया। अब बच्चे न केवल पढ़ाई के लिए बल्कि मनोरंजन, मित्रता, संवाद और रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए भी इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं। डिजिटल तकनीक ने शिक्षा के अवसरों का विस्तार किया है, ज्ञान को अधिक सुलभ बनाया है और बच्चों को वैश्विक दुनिया से जोड़ने का कार्य किया है। लेकिन इसके साथ ही यह दुनिया अनेक अदृश्य खतरों से भी भरी हुई है। साइबर बुलिंग, ऑनलाइन शोषण, फर्जी पहचान, डेटा चोरी, डिजिटल लत और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव जैसे मुद्दे तेजी से बढ़ रहे हैं।

डिजिटल युग में बच्चों की सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू उनकी गोपनीयता और व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा है। आज लगभग हर ऐप, वेबसाइट और ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म उपयोगकर्ताओं की जानकारी एकत्र करता है। बच्चों की उम्र, पसंद, गतिविधियाँ, लोकेशन, मित्रों का नेटवर्क और व्यवहार संबंधी सूचनाएँ डिजिटल कंपनियों के लिए मूल्यवान संसाधन बन गई हैं। समस्या यह है कि अधिकांश बच्चे और उनके अभिभावक यह नहीं समझ पाते कि उनके द्वारा साझा की गई जानकारी का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है। कई बार बच्चे खेल-खेल में अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा कर देते हैं, जिसका दुरुपयोग विज्ञापन कंपनियाँ या अन्य व्यावसायिक संस्थाएँ कर सकती हैं।

इसी संदर्भ में भारत सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) अधिनियम, 2023 लागू किया है। यह कानून व्यक्तिगत डेटा के संग्रह, उपयोग और संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी ढाँचा प्रदान करता है। इस कानून के अंतर्गत बच्चों के डेटा के लिए विशेष सुरक्षा उपाय निर्धारित किए गए हैं। किसी भी डिजिटल मंच को बच्चे की व्यक्तिगत जानकारी संसाधित करने से पहले अभिभावक की सत्यापित सहमति प्राप्त करनी होगी। साथ ही बच्चों को लक्षित विज्ञापनों और व्यवहार आधारित ट्रैकिंग से बचाने का प्रयास किया गया है। यह कानून बच्चों की डिजिटल सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन इसकी प्रभावशीलता उसके वास्तविक क्रियान्वयन पर निर्भर करेगी।

हालाँकि, केवल कानून बना देने से समस्या का समाधान नहीं हो जाता। व्यवहारिक स्तर पर अनेक चुनौतियाँ मौजूद हैं। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में सभी अभिभावकों के पास डिजिटल साक्षरता का समान स्तर नहीं है। कई माता-पिता स्वयं नहीं जानते कि सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म या मोबाइल एप्लिकेशन किस प्रकार डेटा एकत्र करते हैं। परिणामस्वरूप वे बिनापढ़े या समझे सहमति दे देते हैं। इस स्थिति में 'सत्यापित अभिभावकीयसहमति' कई बार केवल एक औपचारिक प्रक्रिया बनकर रह जाती है। इसलिए डिजिटल सुरक्षा के लिए केवल कानूनी प्रावधान पर्याप्त नहीं हैं; जन-जागरूकता और डिजिटल शिक्षा भी उतनी ही आवश्यक है।

बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा का दूसरा महत्वपूर्ण आयाम सोशल मीडिया है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और अन्य प्लेटफ़ॉर्म बच्चों के जीवन काहिस्सा बन चुके हैं। ये मंच रचनात्मकता और संवाद के अवसर तो प्रदान करते हैं, लेकिन साथ ही तुलना, प्रतिस्पर्धा और मान्यता प्राप्त करने की प्रवृत्ति को भी बढ़ावा देते हैं। सोशल मीडिया पर मिलने वाली लाइक्स और कमेंट्स बच्चों के आत्मविश्वास और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। कई बच्चे साइबर बुलिंग, ट्रोलिंग और ऑनलाइन उत्पीड़न का शिकार होतेहैं। लगातार नकारात्मक टिप्पणियाँ उनके मनोवैज्ञानिक विकास पर गहरा प्रभाव डाल सकती हैं। कई शोध यह संकेत देते हैं कि सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग अवसाद, चिंता और आत्मसम्मान में कमी जैसी समस्याओं को जन्म दे सकता है।

ऑनलाइन गेमिंग भी बच्चों की डिजिटल सुरक्षा से जुड़ा एक गंभीर मुद्दा बनकर उभरा है। आधुनिक गेम केवल मनोरंजन का साधन नहीं रह गए हैं, बल्कि वेजटिल डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा बन चुके हैं। इन खेलों में बच्चों को लंबे समय तक जोड़े रखने के लिए मनोवैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग किया जाता है। कई गेम्स में इन-ऐप खरीदारी, पुरस्कार प्रणाली औरप्रतिस्पर्धात्मक तत्व शामिल होते हैं, जो बच्चों को बार-बार खेलने केलिए प्रेरित करते हैं। इसके परिणामस्वरूप डिजिटल लत की समस्या उत्पन्न होती है। कई बार बच्चे अनजाने में आर्थिक

लेन-देन कर बैठते हैं या फिरऐसे लोगों के संपर्क में आ जाते हैं जिनकी पहचान संदिग्ध होती है।

डिजिटल शिक्षा के विस्तार ने भी बच्चों की गोपनीयता के संबंध में नई चिंताएँ पैदा की हैं। आज स्कूल और शैक्षणिक संस्थान उपस्थिति दर्ज करने, असाइनमेंट जमा करने, प्रदर्शन का मूल्यांकन करने और अभिभावकों से संवाद करने के लिए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग कर रहे हैं। इन प्रणालियों के माध्यम से बच्चों के बारे में बड़ी मात्रा में डेटा एकत्र किया जाता है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब इस डेटा के उपयोग और संरक्षण को लेकर स्पष्ट नीतियाँ नहीं होतीं। कई बार शैक्षणिक डेटा और व्यावसायिक हितों के बीच की सीमाएँ धुंधली हो जाती हैं। शिक्षा का उद्देश्य बच्चे के विकास कोबढ़ावा देना है, न कि उसे डेटा उत्पाद में परिवर्तित करना।

डिजिटल सुरक्षा का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू बच्चों की मानसिक और भावनात्मक भलाई से जुड़ा है। इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री की विशालता बच्चों के लिए अवसर और खतरा दोनों प्रस्तुत करती है। हिंसक, अश्लील,भ्रामक या घृणा फैलाने वाली सामग्री तक बच्चों की पहुँच आसान हो सकती है। एल्गोरिदम आधारित सिफारिश प्रणाली बच्चों को लगातार ऐसी सामग्री दिखाती रहती है जो उनके व्यवहार और रुचियों से मेल खाती हो। इससे उनके विचारों और दृष्टिकोणों पर प्रभाव पड़ सकता है। कई बार बच्चे वास्तविक और आभासीदुनिया के बीच संतुलन स्थापित करने में कठिनाई अनुभव करते हैं।

इन चुनौतियों के समाधान के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। सबसे पहले, परिवार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। अभिभावकों को बच्चों के डिजिटल जीवन में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। केवल नियंत्रण या प्रतिबंध पर्याप्त नहीं हैं; संवाद, विश्वास और मार्गदर्शन अधिक प्रभावी उपाय हैं। बच्चों को यह सिखाया जाना चाहिए कि वे अपनी व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित रखें, संदिग्ध संदेशों से सावधान रहें और किसी भी असहज स्थिति में तुरंत अपने माता-पिता या शिक्षकों को सूचित करें।

विद्यालयों की भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। डिजिटल साक्षरता को शिक्षा का अनिवार्य हिस्सा बनाया जाना चाहिए। बच्चों को इंटरनेट के सुरक्षितउपयोग, डेटा गोपनीयता, साइबर सुरक्षा और ऑनलाइन नैतिकता के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए। यदि बच्चे यह समझने लगें कि डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म कैसे कार्य करते हैं और उनके डेटा का उपयोग कैसे किया जाता है, तो वे अधिक जिम्मेदार और सुरक्षित डिजिटल नागरिक बन सकेंगे।

सरकार और प्रौद्योगिकी कंपनियों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। डिजिटल मंचों को 'प्राइवेसी बाय डिज़ाइन' के सिद्धांत को अपनाना चाहिए, अर्थात् उत्पादों और सेवाओं को इस प्रकार विकसित किया जाए कि गोपनीयता और सुरक्षा प्रारंभ से ही उनकी संरचना का हिस्सा हो। बच्चों के लिए विशेषरूप से तैयार किए गए प्लेटफ़ॉर्म में न्यूनतम डेटा संग्रह, पारदर्शी नीतियाँ और मजबूत सुरक्षा उपाय होने चाहिए। साथ ही नियामक संस्थाओं को कानूनों के प्रभावी अनुपालन को सुनिश्चित करना होगा।

हमें यह समझना आवश्यक है कि डिजिटल युग में बच्चों की सुरक्षा केवल तकनीकी सुरक्षा का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह उनके अधिकारों, गरिमा और भविष्य की रक्षा का प्रश्न है। डिजिटल दुनिया बच्चों को असीम संभावनाएँ प्रदान करती है, परंतु इन संभावनाओं का लाभ तभी प्राप्त किया जा सकता है जब सुरक्षा और स्वतंत्रता के बीच संतुलन स्थापित किया जाए। कानून, शिक्षा, तकनीक और सामाजिक जागरूकता के समन्वित प्रयासों से ही ऐसा डिजिटल वातावरण निर्मित किया जा सकता है जहाँ बच्चे केवल इंटरनेट के उपयोगकर्ता न हों, बल्कि सुरक्षित, सशक्त और जागरूक डिजिटल नागरिक के रूप में विकसित हो सकें। यही डिजिटल युग की सबसे बड़ी आवश्यकता और हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है।

भाजपा की जिला कामकाजी बैठक में आगामी कार्ययोजना पर हुई चर्चा

संभागीय संगठन प्रभारी रणवीर सिंह रावत की उपस्थिति में विकास व संगठन विस्तार पर हुआ मंथन

धार। भारतीय जनता पार्टी की मासिक जिला कामकाजी बैठक गुरुवार को भाजपा जिला कार्यालय पर संपन्न हुई। जिसमें आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों की रूपरेखा पर विस्तृत चर्चा की एवं संपन्न कार्यक्रमों की समीक्षा की। बैठक को मुख्य अतिथि भाजपा संभाग प्रभारी एवं प्रदेश उपाध्यक्ष रणवीर सिंह रावत, विशेष अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री क्षेत्रीय सांसद सावित्री ठाकुर भाजपा जिला अध्यक्ष महंत निलेश भारती, विधायक नीना वर्मा, जिला महामंत्री देवेंद्र सोनोने ने संबोधित किया। इस दौरान मंच पर भाजपा पूर्व जिला अध्यक्ष क्रमशः प्रभु राठौड़ दिलीप पटोंदिया मनोज सोमानी, जिला पंचायत अध्यक्ष सरदार सिंह मेड़ा पिछड़ा वर्ग मोर्चा प्रदेश महामंत्री नरेंद्र राठौड़ जिला महामंत्री राकेश पटेल जिला उपाध्यक्ष व जिला टोली संयोजक कपिल निनामा उपस्थित रहे। सर्वप्रथम अतिथियों ने माँ

भारती,पंडित दीनदयाल उपाध्याय व डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्ज्वलित कर की। भाजपा जिलाध्यक्ष भारती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में देश ने विकास, सुशासन और जनकल्याण के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं। उन्होंने केंद्र सरकार की विभिन्न जनहितैषी योजनाओं एवं उपलब्धियों की जानकारी देते हुए कार्यकर्ताओं से इन विकास कार्यों को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया।

केंद्रीय राज्यमंत्री सावित्री ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में देश ने विकास, सुशासन और आत्मनिर्भरता की दिशा में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण, किसानों के उत्थान, युवाओं को रोजगार के अवसर और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारत आज विश्व मंच पर एक मजबूत और प्रभावशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ है। भाजपा के संभाग प्रभारी रावत ने संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा की वास्तविक ताकत उसके समर्पित कार्यकर्ता और मजबूत बूथ संगठन हैं। बूथ स्तर तक सक्रिय संगठन ही पार्टी को लगातार सफलता दिला रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों का कार्यकाल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए समर्पित रहा है। इस दौरान देश ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं तथा भारत की वैश्विक पहचान और प्रतिष्ठा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। केंद्र सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन को और अधिक मजबूत बनाने के लिए बूथ स्तर पर सक्रिय भूमिका निभाने की बात कही। बैठक में सभी मंडल अध्यक्ष, मंडल प्रभारी, कार्यक्रमों के नियुक्त संयोजक-सह संयोजक एवं टोली प्रमुखों से सीधा संवाद किया गया। बूथ स्तर, शक्ति केंद्रों पर संपन्न कार्यों, 'मन की बात' कार्यक्रम एवं संगठन द्वारा निर्देशित अन्य अभियानों की प्रगति की जानकारी ली गई।साथ ही सफल दो-दिवसीय जिला प्रशिक्षण वर्ग के लिए सभी साथियों को धन्यवाद दिया। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी संजय शर्मा ने बताया कि जिला कामकाजी बैठक में जिले के पदाधिकारी सभी 18 मंडल अध्यक्ष एवं मंडल प्रभारी गण मोर्चा अध्यक्ष अभियान टोली सदस्य उपस्थित रहे। बैठक का संचालन जिला महामंत्री राकेश पटेल ने व आभार कपिल निनामा ने माना।

शहर के तापमान को कम करने और भूजल स्तर सुधारने के लिए वन विभाग एवं पुलिस विभाग, धार की अनूठी पहल

डी.आर.पी. लाइन में इस वर्षा ऋतु में रोपे जाएंगे 5000 पौधे, नामकरण के लिए प्रतियोगिता आयोजित

धार। वन मंडल अधिकारी विजयानंथम टी. आर, पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा के संयुक्त प्रयास से वन विभाग, पुलिस विभाग, जिला प्रशासन एवं आम जनता के संयुक्त प्रयासों से शहर के पर्यावरण को सुरक्षित और समृद्ध बनाने के लिए 'विस्तार वानिकी परियोजना' के तहत इस वर्षा त्रतु 2026 में एक वृहद पौधारोपण अभियान की शुरुआत की जा रही है। इस विशेष परियोजना के तहत डी. आर.पी. लाइन क्षेत्र की 10 हेक्टेयर भूमि पर तीव्र गति से बढ़ने वाले और सघन छाया देने वाले 5000 फलदार, औषधीय, छायादार व मिश्रित प्रजाति के पौधे रोपे जाएंगे। योजना अंतर्गत पौधों की आगामी 03 वर्षों तक वन विभाग द्वारा आम जन के सहयोग से सुरक्षा की जावेगी। इस अनूठी हरित पहल को एक प्रभावी और प्रेरणादायक नाम देने के लिए विभाग द्वारा एक 'नामकरण प्रतियोगिता' का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में शहर का कोई भी नागरिक भाग ले सकता है और अपना सर्वश्रेष्ठ सुझाव भेज सकता है।

परियोजना का मुख्य उद्देश्य - इस परियोजना का उद्देश्य डी.आर.पी. लाइन के 2 कि.मी. परिधि क्षेत्र में अगले 4 वर्षों में क्षेत्र के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कमी लाना, भू-जल पुनर्भरण को बढ़ावा देना, शहर के पर्यावरण को सुरक्षित एवं समृद्ध बनाना है।

20+ स्थानीय प्रजातियों का होगा रोपण: - पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करने के लिए जैव-विविधता का विशेष ध्यान रखा गया है। इस 10 हेक्टेयर क्षेत्र में केवल पारंपरिक और पर्यावरण के अनुकूल 20 से अधिक स्थानीय प्रजातियों के पौधे लगाए जाएंगे, जिनमें मुख्य रूप से बरगद, पीपल, नीम, आंवला, बेलपत्र आदि शामिल हैं। ये पौधे न केवल शहर को शुद्ध हवा देंगे बल्कि पक्षियों और छोटे जीवों के लिए एक बेहतरीन रहवास भी बनेंगे।

नामकरण प्रतियोगिता में ऐसे लें भाग: - प्रतियोगिता के लिए भेजे जाने वाले नाम ऐसे होने चाहिए जो वन विभाग, पुलिस विभाग, जिला प्रशासन और जनता के सामूहिक प्रयासों को दर्शाते हों, साथ ही पर्यावरण संरक्षण, शीतलता और जल संचय के उद्देश्य को बखूबी बयां करते हों। नामकरण केवल हिंदी में स्वीकार किये जावेंगे। विजेता नाम का चयन एक विशेष समिति द्वारा किया जाएगा और चयनित नाम का उपयोग इस पूरी परियोजना के मुख्य बोर्ड, सरकारी दस्तावेजों व प्रचार-प्रसार में किया जाएगा। विजेता को विभाग द्वारा पुरुस्कार राशि 1500/- से पुरस्कृत भी किया जाएगा। नागरिक अपने नाम के सुझाव (केवल हिंदी में) 17 जून 2026 तक गूगल फार्म के माध्यम से भेज सकते हैं।

ग्राम तिरमहु में जनकल्याण शिविर 15 जून को

बैतूल। मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी द्वारा आमला ग्रामीण वितरण केंद्र अंतर्गत ग्राम त्रिमहु में 15 जून को जनकल्याण शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर ग्राम पंचायत भवन तिरमहु में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित होगा, जहां उपभोक्ताओं की बिजली संबंधी समस्याओं का मौके पर समाधान किया जाएगा। शिविर में नए घरेलू, कृषि एवं व्यावसायिक बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इसके अलावा गलत या अधिक बिल, मीटर रीडिंग संबंधी शिकायतों का निराकरण किया जाएगा तथा नाम, पता और विद्युत भार में संशोधन की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। उपमहाप्रबंधक (कार्य) विद्युत विभाग, बैतूल वृत्त ने ने बताया कि त्रिमहु फीडर क्षेत्र के उपभोक्ताओं की लो वोल्टेज, फ्यूज ऑफ, ट्रांसफार्मर खराबी, लाइन मरम्मत एवं खंभा शिफ्टिंग जैसी तकनीकी समस्याओं का भी समाधान किया जाएगा। खराब या धीमे चल रहे मीटरों की जांच कर आवश्यकतानुसार उन्हें बदला भी जाएगा। शिविर में केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न विद्युत योजनाओं की जानकारी और लाभ भी उपलब्ध कराया जाएगा। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर रूफटॉप स्थापना के आवेदन लिए जाएंगे, वहीं प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर कृषि पंप से संबंधित जानकारी एवं आवेदन प्रक्रिया की सुविधा भी दी जाएगी। बीपीएल श्रेणी के पात्र उपभोक्ताओं को निशुल्क बिजली कनेक्शन योजना की जानकारी भी प्रदान की जाएगी। इस अवसर पर विद्युत सुरक्षा एवं जागरूकता संबंधी संदेश भी दिए जाएंगे। विभाग ने किसानों एवं ग्रामीणों से अपील की है कि 11 केवी विद्युत लाइनों के नीचे पेड़ न लगाएं, कटी हुई तार या ढीले खंभे दिखाई देने पर तत्काल 1912 पर सूचना दें तथा घरों में उचित अर्थिंग की व्यवस्था कर विद्युत दुर्घटनाओं से बचाव सुनिश्चित करें।

पहली से 12वीं तक के छात्रों की बनना है अपार आईडी, ताकि देखा जा सके उनका शैक्षणिक ब्यौरा

मात्र 67.09 प्रतिशत विद्यार्थियों की बनी अपार आईडी

एस द्विवेदी, बैतूल। पहली से 12वीं तक के विद्यार्थियों को डिजिटल पहचान देने के लिए शुरू किये गये अपार आईडी के अभियान की रफ्तार जिले में बहुत ही धीमी है। आंकड़े बताते हैं कि जिले के 2 लाख 62 हजार 889 पंजीकृत विद्यार्थियों में से अब तक सिर्फ 1 लाख 76 हजार 364 की ही अपार आईडी बन पाई है। यानि करीब 32.91 फीसदी विद्यार्थी आज भी इस सिस्टम से बाहर हैं। दरअसल जिले में आधार कार्ड की तरह हर स्कूली विद्यार्थी का बारह अंकों का अपार कार्ड यानि ऑटोमेटिड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट बनाने का काम चल रहा है, लेकिन इस काम की रफ्तार धीमी होने के कारण जिले में मात्र 67.91 प्रतिशत विद्यार्थियों की ही अपार आईडी बन पाई है। यह हालात शिक्षा विभाग के डिजिटल दावों की पोल खोलते हैं। जिले में 2624 स्कूल संचालित हैं, जहां विद्यार्थियों का डिजिटल शैक्षणिक रिकॉर्ड तैयार करने का लक्ष्य तय किया गया था। पिछले एक साल से प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अब भी 86 हजार 525 विद्यार्थियों की अपार आईडी नहीं बनी। यह आंकड़े साफ इशारा करते हैं कि बड़ी संख्या में विद्यार्थी अपार आईडी के नॉन जनरेट श्रेणी में दर्ज हैं। यह स्थिति या तो अभिभावकों और विद्यार्थियों में जागरूकता की भारी कमी को दर्शाती है, है, या फिर स्कूल स्तर पर गंभीर लापरवाही

को।

पहले युद्धस्तर पर काम, अब फाइलों में दबा अभियान- अपार आईडी की शुरुआत के समय काम युद्धस्तर पर किया गया। समीक्षा बैठकें हुई, लक्ष्य तय किए गए और नोटिस तक जारी हुए। लेकिन कुछ ही महीनों में पूरा अभियान ठंडे बस्ते में चला गया। नतीजा यह है कि हजारों विद्यार्थी अब भी डिजिटल पहचान से वंचित हैं और शिक्षा विभाग की निगरानी व्यवस्था सवालों के घेरे में है। वहीं स्कूल प्रबंधनों का कहना है कि डाटा मिसमैच, आधार व रिकॉर्ड में स्पेलिंग मिसमैच होने से प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही। आधार सुधार केंद्रों की कमी भी इस प्रक्रिया को जटिल बना रही है। पहले स्कूली मार्कशीट के आधार पर सुधार किया जाता था, लेकिन अब यह प्रक्रिया और कठिन हो गई है। स्कूल प्रबंधन लगातार इस समस्या के समाधान में जुटे हैं, लेकिन गति बहुत धीमी है। जिसके कारण भी अपार आईडी का काम प्रभावित हो रहा है। विद्यार्थियों की समग्र आईडी और आधार में समानता नहीं होने के कारण भी परेशानी आ रही है।

शिक्षकों के सामने आ रही कई समस्या - अपार आईडी को लेकर शिक्षकों के सामने भी कई समस्या आ रही है। शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि इस प्रक्रिया में सबसे बड़ी समस्या आधार कार्ड में छोटी-छोटी त्रुटियां होना है। कई मामलों में विद्यार्थियों के नाम की स्पेलिंग, सरनेम सहित अन्य दस्तावेजों से मेल नहीं खाती, सरनेम गायब है या फिर पते में विसंगतियां है। इन समस्याओं को हल करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों को तैयार करने में लंबा समय लग रहा है। जानकार बताते है कि अपार आईडी में विद्यार्थी का नाम, माता-पिता का नाम, जन्मतिथि, जेंडर, आधार नंबर के साथ चाइल्ड प्रोफाइल एंट्री संपूर्ण होने के साथ आधार सत्यापित होना चाहिए। अभिभावक का मोबाइल नंबर और कोई एक पहचान पत्र भी जरूरी है।

जिले में 67.09 प्रतिशत अपार आईडी का काम पूरा - जिले के शासकीय एवं अशासकीय स्कूलों में कक्षा एक से लेकर 12वीं तक लगभग 2 लाख 46 हजार 875 विद्यार्थियों की अपार आईडी बनना है। इन सभी की अपार आईडी बनाने का काम स्कूलों को सौंपा है। अभी तक 1 लाख 86 हजार 359 छात्रों की अपार आईडी बन सकी है, जो कुल दर्ज छात्रों का महज 68.20 प्रतिशत है। बताया जा रहा है कि प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों के कुल 167662 बच्चों में से 108052 की आईडी बन चुकी है, वहीं 9वीं से 12 तक दर्ज छात्रों की संख्या 79213 है। जिसमें से 60307 विद्यार्थियों की आईडी बन चुकी है, जबकि जिले के कुल 2624 स्कूलों में 262889 विद्यार्थी अध्ययनरत है।

12 से 18 जून तक शाहपुर नगर परिषद क्षेत्र में आयोजित होंगे जनकल्याण शिविर

बैतूल। मुख्यमंत्री जनकल्याण अभियान के अंतर्गत नगर परिषद शाहपुर क्षेत्र में 12 जून से 18 जून 2026 तक वार्डवार जनकल्याण शिविरों का आयोजन किया जाएगा। शिविरों में नागरिकों की समस्याओं एवं शिकायतों का निराकरण करने के साथ-साथ विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से संबंधित आवेदनों का परीक्षण एवं निराकरण किया जाएगा। जारी कार्यक्रम के अनुसार 12 जून को वार्ड क्रमांक 1 एवं 2 के लिए आंगनवाड़ी भवन वार्ड क्रमांक 1 में, 13 जून को वार्ड क्रमांक 3 एवं 4 के लिए मंगल भवन वार्ड क्रमांक 3 में, 14 जून को वार्ड क्रमांक 5 एवं 6 के लिए आंगनवाड़ी भवन वार्ड क्रमांक 5 में, 15 जून को वार्ड क्रमांक 7 एवं 8 के लिए आंगनवाड़ी भवन वार्ड क्रमांक 7 एवं 8 में, 16 जून को वार्ड क्रमांक 9 से 11 के लिए आंगनवाड़ी भवन वार्ड क्रमांक 9 में, 17 जून को वार्ड क्रमांक 12 एवं 13 के लिए आंगनवाड़ी भवन वार्ड क्रमांक 12 एवं 13 में तथा 18 जून को वार्ड क्रमांक 14 एवं 15 के लिए आंगनवाड़ी भवन वार्ड क्रमांक 15 में शिविर आयोजित किए जाएंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेहरू के कार्यकाल का तोड़ा रिकॉर्ड, पोस्टर लगे बेमिसाल 12 साल

सोहागपुर । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिकार्ड को तोड़ दिया है। इससे पूरे देश में उत्सव का माहौल है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफल 12 वर्ष पूर्ण होने पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।इसी तारतम्य में सोहागपुर भारतीय जनता पार्टी मंडल के तत्वावधान में भव्य धार्मिक और मंगलमय कार्यक्रम का आयोजन पुराने थाने के पीछे काली मंदिर एवं हनुमान मंदिर इस गौरवमयी उपलब्धि विशेष पूजा-अर्चना और सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया गया। जिसमें देश की प्रगति और दीर्घायु के लिए प्रार्थनाकार्यक्रम की शुरुआत भगवान हनुमान जी की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित किया गया।। इसके उपरांत उपस्थित भाजपा पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और स्थानीय श्रद्धालुओं ने सामूहिक रूप से सुंदरकांड का पाठ किया। इस अवसर पर पंडितों द्वारा विशेष हवन-पूजन भी संपन्न कराया गया। जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के

उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और देश की निरंतर प्रगति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई। सुन्दर काण्ड संगीतमय हुए। इस अवसर पर उत्साह से लबरेज़ समारोह के अवसर पर सोहागपुर भाजपा मंडल के वक्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। नेताओं ने कहा कि इन 12 वर्षों में देश ने विकास और जनकल्याण के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। सुंदरकांड पाठ के समापन पर भगवान की महाआरती की गई । उपस्थित सभी नागरिकों एवं श्रद्धालुओं को प्रसाद का वितरण किया गया।इस अवसर पर सोहागपुर मंडल के प्रमुख पदाधिकारी, वरिष्ठ नेता, मातृशक्ति और बड़ी संख्या में स्थानीय भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इधर राज्य मार्ग पिपरिया नर्मदापुरम पर नगर की पलकमती नदी पुल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्षेत्रीय विधायक विजयपालसिंह एवं नगर पंचायत परिषद अध्यक्ष श्रीमती लता यशवंत पटेल के होर्डिंग्स लगाए गए। जिसमें लिखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र के बेमिसाल 12 साल। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्दाबाद के नारे लगाकर खुशी का इजहार किया गया।

राष्ट्रपति के प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों का केंद्रीय मंत्री ने लिया जायजा

बैतूल। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु के मुख्य आतिथ्य में 18 जून को प्रस्तावित आध्यात्मिक जागृति से जनजातीय समाज का सशक्तिकरण कार्यक्रम की तैयारियों का केंद्रीय राज्यमंत्री एवं सांसद बैतूल दुर्गादास उईके ने जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर की जा रही व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान विधायक मुलताई चंद्रशेखर देशमुख, विधायक आमला डॉ. योगेश पंडाग्रे, जिला पंचायत अध्यक्ष राजा पवार, जिला पंचायत उपाध्यक्ष हंसराज धुर्वे, कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे, पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन सहित जनप्रतिनिधि एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

जनजातीय ग्रामों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने में कोई कसर न छोड़ी जाए: केंद्रीय मंत्री

दस्तावेज और जानकारी के अभाव में कोई पात्र हितग्राही योजनाओं से वंचित न रहे

बैतूल। केंद्रीय राज्यमंत्री एवं सांसद बैतूल दुर्गादास उईके ने कहा है कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान जनजातीय क्षेत्रों के समग्र विकास की महत्वपूर्ण योजना है। जिले के चिन्हित सभी 554 जनजातीय ग्रामों में सडक़, बिजली, पेयजल, मोबाइल नेटवर्क सहित सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी जाए। उन्होंने कहा कि इन कार्यों के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध है तथा जहां भी समस्याएं आ रही हैं, उनका विभागीय समन्वय से स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जाए। केंद्रीय मंत्री श्री उईके जिला विकास समन्वय एवं जिला निगरानी समिति दिशा की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में विधायक भैंसदेही महेंद्र सिंह चौहान, विधायक मुलताई चंद्रशेखर देशमुख, विधायक आमला डॉ. योगेश पंडाग्रे, जिला पंचायत अध्यक्ष राजा पवार, जिला पंचायत उपाध्यक्ष हंसराज धुर्वे, कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे, पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन, वनमंडलाधिकारी नवीन गर्ग, वनमंडलाधिकारी अरिहंत कोचर सहित जनप्रतिनिधि एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में केंद्रीय मंत्री श्री उईके ने निर्देश दिए कि दस्तावेजों या जानकारी के अभाव में योजनाओं से वंचित पात्र हितग्राहियों को चिन्हित कर उन्हें लाभान्वित किया जाए तथा शत-प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित की जाए। उन्होंने स्वीकृत निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि स्कूल, आंगनवाड़ी और अन्य सार्वजनिक भवनों की डीपीआर में बाउंड्रीवाल, शौचालय, पेयजल व्यवस्था तथा शिक्षकों के आवास को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए। पंचायतों में उपलब्ध खर्च नहीं की गई राशि की कार्ययोजना बनाकर प्राथमिकता वाले कार्य पूर्ण करने के भी निर्देश दिए।

पीएम आवासों को शीघ्र पूर्ण कराये - प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की समीक्षा करते हुए उन्होंने लंबित आवासों को गुणवत्तापूर्ण ढंग से शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित न रहे तथा लाभ वितरण में पूर्ण पारदर्शिता बरती जाए। योजनाओं में अनियमितता की शिकायत मिलने पर संबंधित अधिकारियों एवं सचिवों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने तथा पात्रता एवं स्वीकृति प्रक्रिया को लेकर व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने के निर्देश भी दिए।

जर्मनी के कॉन्सुलेट जनरल क्रिस्टोफ हॉलियर ने किया इंदौर एवं पीथमपुर का दो-दिवसीय दौरा

औद्योगिक, आईटी और पर्यटन संभावनाओं को सराहा; बोले जर्मन उद्योगों के लिए आकर्षक केंद्र के रूप में उभर रहा है यह क्षेत्र

धार। भारत और जर्मनी के बीच आर्थिक एवं औद्योगिक सहयोग को नई गति देने के उद्देश्य से जर्मनी के कॉन्सुलेट जनरल श्री क्रिस्टोफ हॉलियर (Christoph Hallier) ने 10 एवं 11 जून को इंदौर तथा पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र का दो-दिवसीय विस्तृत दौरा किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र की औद्योगिक अधोसंरचना, सूचना प्रौद्योगिकी (IT) और पर्यटन संभावनाओं का बारीकी से अवलोकन किया।

इंदौर की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर की सराहना - अपने दो-दिवसीय दौरे के प्रथम दिन, 10 जून को कॉन्सुलेट जनरल श्री हॉलियर ने इंदौर के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहर स्थलों 'लालबाग पैलेस' तथा 'राजवाड़ा पैलेस' का भ्रमण किया। उन्होंने इंदौर की समृद्ध विरासत, अद्वितीय स्थापत्य कला और पर्यटन क्षमता की मुक्त कंठ से सराहना करते हुए इसे अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के लिए एक बेहद

आकर्षक गंतव्य बताया।

पीथमपुर के उद्योगों और इंदौर के आईटी इकोसिस्टम का अवलोकन - दौरे के दूसरे दिन, 11 जून को उन्होंने धार जिले के प्रमुख औद्योगिक क्लस्टर पीथमपुर स्थित 'हेटिच इंडिया' (Hettich India) की इकाई, 'माहले आनंद थर्मल सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड' (Mahle Anand Thermal Systems Private Limited) की उत्पादन इकाई तथा इंदौर स्थित 'इन्फोबीन्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड' (InfoBeans Technologies Limited) का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने यहां की आधुनिक उत्पादन प्रक्रियाओं, तकनीकी नवाचारों, विश्वस्तरीय औद्योगिक अधोसंरचना तथा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की बढ़ती क्षमताओं को निकट से समझा।

निवेश अवसरों और औद्योगिक परिवेश पर विस्तृत चर्चा - दौरे के दौरान मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम (MPIDC) इंदौर के कार्यकारी संचालक हिमांशु प्रजापति उनके साथ विशेष रूप से उपस्थित रहे। प्रजापति ने कॉन्सुलेट जनरल को इंदौर-पीथमपुर क्षेत्र के उत्कृष्ट औद्योगिक परिवेश, निवेश के नए अवसरों, तेजी से विकसित हो रहे लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, मजबूत आईटी इकोसिस्टम तथा व्यापारिक संभावनाओं की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने क्षेत्र में उपलब्ध विश्वस्तरीय अवसंरचना, कुशल मानव संसाधन तथा निवेशकों के लिए सरकार द्वारा दी जा रही विभिन्न सुविधाओं पर भी प्रकाश डाला।

भारत-जर्मनी व्यापारिक संबंधों में मध्य प्रदेश की भूमिका महत्वपूर्ण - भ्रमण के उपरांत अपने विचार साझा करते हुए जर्मनी के कॉन्सुलेट जनरल श्री हॉलियर ने कहा कि 'भारत, जर्मनी का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच व्यापार एवं निवेश संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं और मध्य प्रदेश का इंदौर-पीथमपुर क्षेत्र औद्योगिक एवं तकनीकी सहयोग की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण संभावनाएं रखता है।' उन्होंने पूर्ण विश्वास व्यक्त किया कि इंदौर एवं पीथमपुर भविष्य में जर्मन उद्योगों और निवेशकों के लिए और अधिक आकर्षक केंद्र के रूप में उभरेंगे। कॉन्सुलेट जनरल का यह दौरा आने वाले समय में धार जिले के पीथमपुर और इंदौर क्षेत्र में विदेशी निवेश तथा भारत-जर्मनी आर्थिक सहयोग को एक नई ऊंचाई प्रदान करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने राजनीति को सत्ता का माध्यम नहीं, राष्ट्रसेवा का सर्वोच्च साधन बनाया

आज विश्व भारत को निर्णायक शक्ति, विश्वसनीय साझेदार और भविष्य के नेतृत्वकर्ता के रूप में देखता है

राजेन्द्र शुक्ल

भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में कुछ क्षण ऐसे हैं जो केवल राजनीतिक उपलब्धि नहीं होते, बल्कि राष्ट्र की सामूहिक आकांक्षाओं और विश्वास का प्रतीक बन जाते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के देश की जनता के निरंतर विश्वास के साथ ऐतिहासिक जनादेश प्राप्त कर दीर्घकाल तक राष्ट्र का नेतृत्व करने का अवसर प्राप्त करना गौरवपूर्ण क्षण है। यह केवल एक व्यक्ति की सफलता नहीं, बल्कि नए भारत के निर्माण के संकल्प, सेवा और सुशासन की विजय है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने राजनीति को सत्ता का माध्यम नहीं, बल्कि राष्ट्रसेवा का सर्वोच्च साधन बनाया। उनके नेतृत्व में भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी एक नई पहचान स्थापित की है। आज विश्व भारत को केवल एक बड़ा बाजार नहीं, बल्कि एक निर्णायक शक्ति, विश्वसनीय साझेदार और भविष्य के नेतृत्वकर्ता के रूप में देखता है। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की आवाज पहले से कहीं अधिक प्रभावशाली हुई है और यह परिवर्तन प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच तथा निर्णायक नेतृत्व का परिणाम है।

प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित होना केवल राजनीतिक उपलब्धि नहीं, यह भारत की जनता के अटूट विश्वास और स्नेह का प्रतीक है। निरंतर जनसमर्थन किसी पद या प्रचार से नहीं, बल्कि सेवा, समर्पण, पारदर्शिता, निर्णायक नेतृत्व और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने की कार्यशैली से अर्जित होता है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने स्वयं को सदैव 'प्रधानसेवक' के रूप में प्रस्तुत किया और गरीब, किसान, महिला, युवा तथा समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का सतत प्रयास किया। यही कारण है कि देश की जनता ने बार-बार उन पर अपना विश्वास व्यक्त किया। उनका सादगीपूर्ण व्यक्तित्व, अथक कार्यशक्ति, दूरदर्शी सोच और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का स्पष्ट संकल्प करोड़ों भारतीयों को प्रेरित करता है तथा उन्हें जन-जन का प्रिय नेता बनाता है।

प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने आत्मनिर्भरता, डिजिटल क्रांति, आधारभूत संरचना, रक्षा क्षमता, अंतरिक्ष विज्ञान और आर्थिक सुधारों के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। जनधन, उज्ज्वला, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, हर घर जल, स्वच्छ भारत मिशन, पीएम किसान सम्मान निधि और डिजिटल इंडिया जैसे अनेक कार्यक्रमों ने करोड़ों नागरिकों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया है। शासन की योजनाएँ पहली बार अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पारदर्शी ढंग से पहुँची हैं।

भारतीय संस्कृति और आस्था के पुनर्जागरण का यह कालखंड इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में रहेगा अंकित - भारतीय संस्कृति और आस्था के पुनर्जागरण का भी यह कालखंड इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेगा। अयोध्या में प्रभु श्रीराम के भव्य मंदिर का निर्माण और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करोड़ों भारतीयों की सदियों पुरानी आस्था की पूर्ति का क्षण था। यह केवल मंदिर निर्माण नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना और आत्मगौरव का पुर्नस्थापन था। जम्मू-कश्मीर से संबंधित ऐतिहासिक निर्णयों ने राष्ट्रीय एकीकरण को नई मजबूती प्रदान की। विकास और लोकतंत्र की मुख्यधारा से जुड़ते हुए जम्मू-कश्मीर आज नए अवसरों की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री जी ने यह सिद्ध किया कि दृढ़ इच्छाशक्ति और स्पष्ट नीति के साथ कठिन से कठिन निर्णय भी राष्ट्रहित में लिए जा सकते हैं।

मध्यप्रदेश को प्रधानमंत्री श्री मोदी का विशेष स्नेह और मार्गदर्शन का निरंतर लाभ प्राप्त हुआ है - मध्यप्रदेश प्रधानमंत्री श्री मोदी के विशेष स्नेह और मार्गदर्शन का लाभ निरंतर प्राप्त करता रहा है। प्रदेश में सड़क, रेल, सिंचाई, ऊर्जा, शहरी विकास और स्वास्थ्य क्षेत्र में अभूतपूर्व निवेश एवं परियोजनाओं ने विकास को नई गति दी है। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से गरीब, किसान, महिला और युवाओं के जीवन में बदलाव लाने वाली अनेक योजनाओं का प्रभाव प्रदेश के प्रत्येक जिले तक पहुँचा है। विंध्य क्षेत्र और विशेष रूप से मेरा गृहक्षेत्र रीवा भी इस परिवर्तनकारी यात्रा का साक्षी बना है। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट ने न केवल मध्यप्रदेश बल्कि पूरे देश को स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में नई पहचान दिलाई। यह परियोजना प्रधानमंत्री जी के उस विजन का प्रतीक है जिसमें विकास और पर्यावरण संरक्षण साथ-साथ चलते हैं। आज रीवा देश के ऊर्जा मानचित्र पर एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और विंध्य की पहचान नई संभावनाओं से जुड़ चुकी है। विंध्य क्षेत्र में सड़क संपर्क, रेल सुविधाओं, शिक्षा संस्थानों और आधारभूत संरचना के विस्तार ने विकास के नए द्वार खोले हैं। यह क्षेत्र अब पिछड़ेपन की पहचान से आगे बढ़कर प्रगति और संभावनाओं के केंद्र के रूप में उभर रहा है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और केंद्र सरकार का सतत सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है।

स्वास्थ्य मंत्री के रूप में मुझे यह अनुभव करने का अवसर मिला है कि प्रधानमंत्री जी की सोच केवल इलाज तक सीमित नहीं है, बल्कि स्वस्थ भारत के व्यापक निर्माण की है। आयुष्मान भारत जैसी ऐतिहासिक योजना ने गरीब परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की है। मेडिकल कॉलेजों के विस्तार, स्वास्थ्य अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण, आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं और जनकल्याणकारी स्वास्थ्य योजनाओं ने मध्यप्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा दी है। प्रदेश सरकार भी प्रधानमंत्री जी के इसी दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए प्रत्येक नागरिक तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएँ पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है।

प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का नेतृत्व हमें यह विश्वास देता है कि विकसित भारत का संकल्प केवल एक सपना नहीं, बल्कि एक साकार होती राष्ट्रीय यात्रा है। उनके नेतृत्व में भारत ने आत्मविश्वास, सांस्कृतिक गौरव और विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। आज प्रत्येक भारतीय गर्व के साथ कह सकता है कि उसका देश विश्व पटल पर नई ऊँचाइयों को छू रहा है। व्यक्तिगत रूप से मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे ऐसे युगनिर्माता नेतृत्व के साथ कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है। भारतीय चिंतन में आदर्श नेतृत्व का आधार सदैव लोककल्याण और राष्ट्रहित रहा है।

'प्रजासुखे सुखं राज्ञः प्रजानां च हिते हितम्।
नात्मप्रियं हितं राज्ञः प्रजानां तु प्रियं हितम्॥ '

शासक का सुख प्रजा के सुख में और उसका हित प्रजा के हित में निहित होता है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में जनसेवा, सुशासन और राष्ट्र प्रथम की यही भावना निरंतर परिलक्षित होती है। मध्यप्रदेश और विंध्य की जनता की ओर से मैं उनके प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ तथा ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वे उन्हें उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और राष्ट्रसेवा की अक्षुण्ण ऊर्जा प्रदान करें, ताकि उनके नेतृत्व में भारत विकसित, आत्मनिर्भर और विश्वगुरु बनने की दिशा में निरंतर अग्रसर रहे।

(लेखक मध्यप्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं)

संक्षिप्त समाचार

राजस्व मंत्री ने भाउखेड़ी मनरेगा पार्क में किया पौधारोपण

झाड़ू लगाकर दिया स्वच्छता का संदेश

सीहोर (निप्र)। इछावर के भाऊखेड़ी मनरेगा पार्क में पौधरोपण एवं स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राजस्व मंत्री श्री करण सिंह वर्मा ने पौधारोपण किया और झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता दोनों ही समाज की सामूहिक जिम्मेदारी हैं। बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को देखते हुए प्रत्येक नागरिक को अधिक से अधिक पौधे लगाने तथा उनकी देखभाल करने का संकल्प लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि वृक्ष न केवल पर्यावरण को संतुलित बनाए रखते हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ और सुरक्षित भविष्य भी प्रदान करते हैं। राजस्व मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि स्वच्छता केवल एक अभियान नहीं, बल्कि जीवनशैली का हिस्सा बननी चाहिए। स्वच्छ वातावरण से स्वास्थ्य बेहतर रहता है और समाज में सकारात्मक परिवर्तन आता है। उन्होंने उपस्थित लोगों से अपने घर, गांव और आसपास के क्षेत्रों को स्वच्छ रखने तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए सक्रिय सहभागिता निभाने का आह्वान किया।

रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर प्रशासन की सख्त कार्रवाई

संयुक्त टीम ने डंपर एवं दो ट्रैक्टर-ट्रॉली किए जप्त

नर्मदापुरम (निप्र)। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा के निर्देशानुसार जिले में रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के विरुद्ध लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में शिकायत प्राप्त होने पर दिनांक 07 जून 2026 की रात्रि राजस्व,

खनिज एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा ग्राम आंचलखेड़ा, तहसील माखननगर में कार्रवाई करते हुए रेत का अवैध उत्खनन कर रहे एक डंपर क्रमांक एमपी04एचई5029 को जप्त किया गया। जप्त वाहन को पुलिस थाना माखननगर की अभिरक्षा में रखा गया है। इसी प्रकार दिनांक 08 जून 2026 को खनिज निरीक्षक द्वारा ग्राम मगरिया, तहसील नर्मदापुरम् क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए रेत का अवैध परिवहन कर रहे दो ट्रैक्टर-ट्रॉली जप्त किए गए। दोनों वाहनों को पुलिस थाना देहात नर्मदापुरम् की अभिरक्षा में रखा गया है। प्रशासन द्वारा संबंधित वाहनों के विरुद्ध म.प्र. खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण का निवारण) नियम 2022 के प्रावधानों के तहत वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध उत्खनन एवं परिवहन में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध आगे भी लगातार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

कलेक्टर के निर्देश पर मालेगांव में ग्रामीणों की पेयजल समस्या का तत्काल हुआ समाधान

बैतूल (निप्र)। जिले के अंतिम छोर पर स्थित एवं बैतूल के सबसे ऊंचे स्थानों में बसे भैंसदेही विकासखंड के ग्राम मालेगांव में पेयजल समस्या बनी हुई थी। इस संबंध में ग्रामवासियों द्वारा जनसुनवाई में कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे को आवेदन प्रस्तुत किया गया था। समस्या को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग पीएचई के कार्यपालन यंत्री को तत्काल आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। निर्देशों के पालन में कार्यपालन यंत्री पीएचई श्री मनोज बघेल द्वारा स्वयं स्थल का निरीक्षण किया गया।

रेत के अवैध भण्डारण, परिवहन पर राजस्व, पुलिस एवं खनिज अमला की बड़ी कार्यवाही

2 जेसीबी मशीन, 2 डम्पर एवं 7 ट्रेक्टर किए जप्त

बैतूल (निप्र)। कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे के निर्देशानुसार जिले में अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत 8 जून को घोड़ाडोंगरी तहसील के ग्राम चिखलपाटी की भड़ंगा नदी क्षेत्र में खनिज रेत के अवैध उत्खनन एवं भण्डारण की सूचना मिलने पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शाहपुर के नेतृत्व में राजस्व, पुलिस एवं खनिज अमले द्वारा संयुक्त रूप से छापामार कार्यवाही करते हुए उक्त क्षेत्र का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। मौका निरीक्षण के दौरान अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शाहपुर, तहसीलदार घोड़ाडोंगरी, नायब तहसीलदार चोपना, हल्का पटवारी, पुलिस थाना चोपना का पुलिस बल खनि निरीक्षक एवं सहायक खनि अधिकारी बैतूल द्वारा मौका निरीक्षण के दौरान उक्त नदी क्षेत्र स्थित शासकीय भूमि ख. क्र.475 रकबा 9.100 हेक्टेयर क्षेत्र में से रेत उत्खनन कर नदी के किनारे ग्राम चिकलपाटी की भूमि ख. क्र. 474 रकबा 64.947 हेक्टेयर मद बड़े झाड़ का जंगल में 02 अलग-अलग ढेर के रूप में खनिज रेत का अवैध भण्डारण करना पाया गया, जिसमें से एक ढेर में खनिज रेत की मात्रा 210 घन मीटर एवं दूसरे ढेर में खनिज रेत की मात्रा 120 घन मीटर पाई गई। इस प्रकार खनिज रेत की कुल मात्रा 330 घन मीटर का मौके पर भण्डारण पाया गया। इसके साथ ही मौके पर 07 ट्रेक्टर-ट्राली में से 03 ट्रैक्टर-ट्राली एवं 01 डम्पर खनिज रेत से भरा पाया गया।

■ राशन हितग्राहियों को शत-प्रतिशत राशन वितरण और ईकेवाईसी करने के कलेक्टर ने दिए निर्देश, कलेक्टर ने की कृषि, खाद्य, औषधि प्रशासन और खाद्य सुरक्षा की समीक्षा

जिले में सुनिश्चित की जाए डीजल, पेट्रोल और गैस की सुचारू आपूर्ति : कलेक्टर

सीहोर (निप्र)। कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कृषि, खाद्य, औषधि प्रशासन एवं खाद्य सुरक्षा विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित कर विभागीय गतिविधियों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आम नागरिकों और किसानों को आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए तथा सभी व्यवस्थाएं समय पर और सुचारू रूप से संचालित की जाएं। खाद्य विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने निर्देश दिए कि पात्र हितग्राहियों को राशन का शत-प्रतिशत वितरण सुनिश्चित किया जाए तथा सभी हितग्राहियों की केवाईसी प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण की जाए। उन्होंने कहा कि राशन का उठाव और वितरण निर्धारित समय पर होना चाहिए, ताकि किसी भी पात्र परिवार को खाद्यान्न प्राप्त करने में कठिनाई न आए। कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने जिले में डीजल, पेट्रोल एवं एलपीजी गैस की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के निर्देश देते हुए कहा कि अधिकारी पेट्रोल पंपों का नियमित निरीक्षण करें और आपूर्ति व्यवस्था पर सतत निगरानी रखें। उन्होंने विशेष रूप से निर्देश दिए कि किसानों को कृषि कार्यों के लिए आवश्यक डीजल की उपलब्धता में किसी प्रकार की बाधा न आए। कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने डीएपी, एनपीके सहित उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खेती के सीजन में किसानों को खाद के लिए भटकना न पड़े। साथ ही उर्वरकों की कालाबाजारी पर सख्त नजर रखने और संबंधितों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों को ई-विकास पोर्टल से जनरेट टोकन के आधार पर पात्रतानुसार एवं नियमानुसार ही उर्वरकों का वितरण किया जाए। खाद्य सुरक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने निर्देश दिए कि मिलावट के विरुद्ध की गई कार्रवाइयों में लगाए गए जुर्माने की वसूली समय पर सुनिश्चित की जाए तथा लंबित प्रकरणों का त्वरित निराकरण किया जाए। उन्होंने खाद्य प्रतिष्ठानों और दुकानों का नियमित निरीक्षण कर मिलावटखोरों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई जारी रखने के निर्देश भी दिए। औषधि प्रशासन विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने निर्देश दिए कि जिले में दवाओं की गुणवत्ता एवं उपलब्धता पर सतत निगरानी रखी जाए।

उन्होंने कहा कि मेडिकल स्टोर्स और औषधि प्रतिष्ठानों का नियमित निरीक्षण किया जाए तथा अमानक, नकली अथवा एक्सपायरी दवाओं के विक्रय पर सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही आवश्यक जीवनरक्षक दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए आमजन को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण औषधियां उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने कहा कि आमजन को गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना, किसानों को समय पर खाद एवं ईंधन उपलब्ध कराना तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रभावी बनाए रखना प्रशासन का दायित्व है। इसके लिए सभी विभाग समन्वय के साथ कार्य करते हुए शासन की योजनाओं और व्यवस्थाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। बैठक में कृषि उप संचालक श्री अशोक कुमार उपाध्याय, जिला आपूर्ति अधिकारी श्रीमती रेशमा भामोर सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

विश्व योग दिवस की तैयारियों का अंशुल गुप्ता ने लिया जायजा

विदिशा (निप्र)। अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिवस 21 जून को आयोजित होने वाले सामूहिक योग के विभिन्न स्तरों पर आयोजित कार्यक्रम की व्यवस्थाओं का जायजा कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता ने मंगलवार को अपने चेम्बर में समीक्षा कर विभागो के अधिकारियों को आवश्यक जबावदेही सौंपी है।

कलेक्टर श्री गुप्ता ने कहा कि जिले के सभी प्राकृतिक व पुरातत्व धरोहर स्थलो के साथ-साथ पर्यटन स्थलो पर सामूहिक योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। योग कार्यक्रम में अधिक से अधिक सहभागिता, गणमान्य नागरिको व स्कूली व महाविद्यालयीन विद्यार्थियों की हो ततसंबंध में विभागो के अधिकारियों को उचित मार्गदर्शन दिया गया है। जिला मुख्यालय व अन्य मुख्यालयो पर पूर्व वर्षो की भांति योग कार्यक्रम होंगे इन ही तर्ज पर सभी हाई स्कूलो व महाविद्यालयों, आईटीआई में भी योग कार्यक्रम आयोजित कर सामूहिक योग को बढाने पर बल दिया है। उक्त बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री ओपी सनोड़िया के द्वारा जिला, विकासखण्ड एवं ग्राम स्तर पर आयोजित होने वाले सामूहिक योग कार्यक्रम की जानकारियां सांझा करते हुए उन्होंने बताया कि तीनो स्तरो पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। जिले के सभी अमृत सरोवर तालाबो के किनारे तथा पुरातत्व धरोहर व पर्यटन स्थल बासौदा में नीलकंठेश्वर मंदिर एवं उदयगिरी में सामूहिक योग कार्यक्रम का आयोजन विशेष तौर पर किया जाएगा। जिला पंचायत सीईओ ने बताया कि 21 जून को जिले के विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित सामूहिक योग कार्यक्रमों में व्यवस्थाओं के लिए आयुष विभाग , शिक्षा विभाग, इसी प्रकार विकासखण्ड मुख्यालयो पर जनपद सीईओ, मुख्य नगरपालिका अधिकारी व खण्ड शिक्षा अधिकारी को संयुक्त रूप से वहीं ग्राम स्तरीय कार्यक्रमो का दायित्व पूर्व उल्लेखित विभागो के ग्राम स्तरीय अमले को सौंपा गया है।

समान नागरिक संहिता से सामाजिक समरसता और समानता को मिलेगा बल : प्रो. गोपाल शर्मा

▶▶ यूसीसी पर जनप्रतिनिधियों, राजनैतिक दलों के सदस्यों, विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों तथा आम नागरिकों ने दिये सुझाव

सीहोर (निप्र)। समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के अध्ययन एवं परीक्षण के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता समिति के सदस्य प्रो. गोपाल शर्मा ने की। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों, सामाजिक, धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों, शांति समिति के सदस्यों, पत्रकारों एवं प्रबुद्ध नागरिकों ने यूसीसी पर अपने सुझाव दिये।

बैठक में समिति के सदस्य प्रो. गोपाल शर्मा ने कहा कि समान नागरिक संहिता से समाज में सद्भाव एवं सौहार्द की स्थापना होगी तथा पारिवारिक और सामाजिक संबंधों में अनावश्यक तनाव की स्थिति नहीं बनेगी। उन्होंने कहा कि यह एक गंभीर एवं महत्वपूर्ण विषय है, जिस पर प्रदेश सरकार नागरिकों की राय लेकर व्यापक अध्ययन कर रही है। यूसीसी लागू होने से महिलाओं, बच्चों एवं सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित होगा तथा विवाह, विवाह विच्छेद, उत्तराधिकार एवं अन्य पारिवारिक विषयों में समानता स्थापित होगी। प्रो. शर्मा ने कहा कि पुरुष और महिलाओं के अधिकारों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रहेगा तथा दत्तक पुत्र को भी जेनेटिक पुत्र के समान अधिकार प्राप्त होंगे। उन्होंने बताया कि वर्तमान में विभिन्न धर्म एवं समुदायों के लिए अलग-अलग पारिवारिक कानून प्रचलित हैं। विवाह, विवाह विच्छेद, भरण-पोषण, उत्तराधिकार तथा लिव-इन संबंध जैसे विषय समान नागरिक संहिता की परिधि में आते हैं।

प्रो. शर्मा ने बताया कि प्रदेश सरकार यूसीसी के संबंध में नागरिकों के विचार एवं सुझाव प्राप्त करने के लिए ucc-mp-gov-in पोर्टल संचालित कर रही है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे पोर्टल पर अपने सुझाव दर्ज कर इस महत्वपूर्ण विषय पर चल रहे जन-विमर्श में सहभागी बनें। बैठक के दौरान यूसीसी से जुड़े सामाजिक, विधिक एवं प्रशासनिक पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

उपस्थित नागरिकों ने विभिन्न राज्यों में लागू व्यवस्थाओं, सामाजिक समरसता, महिला अधिकारों तथा संवैधानिक प्रावधानों से जुड़े महत्वपूर्ण सुझाव समिति के समक्ष रखे। बैठक में सीहोर जनपद अध्यक्ष श्रीमती नावड़ी बाई, संयुक्त कलेक्टर श्री रविन्द्र परमार, एसडीएम श्री तन्मय वर्मा, एसडीओपी श्रीमती पूजा शर्मा सहित विभिन्न राजनैतिक दलों, सामाजिक, धार्मिक संस्थाओं तथा आम नागरिकों द्वारा यूसीसी पर सुझाव दिये गये।

● जल जीवन मिशन बना महिलाओं के सम्मान, सुविधा और सशक्तिकरण का आधार

घर-घर पहुंचा नल का जल, बदली श्रीमती मंजू वर्धन की जिंदगी

सीहोर (निप्र)। सीहोर जिले की रेहटी तहसील के ग्राम अमीरगंज में रहने वाली श्रीमती मंजू वर्धन के जीवन में जल जीवन मिशन के तहत संचालित नल-जल योजना ने एक बड़ा सकारात्मक बदलाव लाया है। कभी प्रतिदिन पानी की व्यवस्था करना उनके दिन का सबसे कठिन और समय लेने वाला काम हुआ करता था, लेकिन आज उनके घर के आंगन में लगे नल से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो रहा है। इससे न केवल उनकी दैनिक परेशानियां कम हुई हैं, बल्कि उनके जीवन की गुणवत्ता में भी उल्लेखनीय सुधार आया है।श्रीमती मंजू वर्धन बताती हैं कि पहले उन्हें पानी के लिए काफी दूर तक जाना पड़ता था। गर्मी के दिनों में स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण हो जाती थी। परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए कई बार दिन में अनेक चक्कर लगाने पड़ते थे, जिससे समय और श्रम दोनों की अधिक खपत होती थी। पानी लाने में लगने वाले समय के कारण घर के अन्य कार्यों पर भी प्रभाव पड़ता था। उन्होंने बताया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत गांव में नल-जल योजना शुरू होने के बाद अब घर पर ही नियमित रूप से पानी उपलब्ध हो रहा है। इससे उन्हें बड़ी राहत मिली है। अब पानी के लिए अधिक दूरी तय नहीं

करनी पड़ती और बचा हुआ समय परिवार की देखभाल तथा अन्य उपयोगी कार्यों में लगाया जा रहा है। श्रीमती मंजू वर्धन का कहना है कि घर तक पानी पहुंचने से महिलाओं का जीवन काफी आसान हुआ है। पहले जहां पानी की चिंता दिनभर बनी रहती थी, वहीं अब स्वच्छ पेयजल सहज रूप से उपलब्ध होने लगा है। इससे परिवार के स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है तथा जीवन अधिक सुविधाजनक और सम्मानजनक बना है। ग्राम अमीरगंज में जल जीवन मिशन के माध्यम से घर-घर नल कनेक्शन उपलब्ध कराकर ग्रामीणों को मूलभूत सुविधा से जोड़ा गया है। श्रीमती मंजू वर्धन की कहानी इस बात का प्रमाण है कि जल जीवन मिशन केवल पेयजल उपलब्ध कराने की योजना नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण महिलाओं के जीवन में बदलाव लाने, उनके श्रम को कम करने और उन्हें सशक्त बनाने का एक प्रभावी माध्यम भी बन रहा है।

आज श्रीमती मंजू वर्धन जल जीवन मिशन के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र और मुख्यमंत्री डॉ मोहन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहती हैं कि नल-जल योजना ने उनके परिवार के जीवन को आसान और बेहतर बनाया है। उनकी यह कहानी ग्रामीण विकास और जनकल्याण की दिशा में जल जीवन मिशन की सफलता का जीवंत उदाहरण है।

मप्र में राष्ट्रपति का सबसे लंबा 5 दिवसीय दौरा

- कूनो नेशनल पार्क आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू

श्योपुर (नप्र)। दुनिया भर में चीता पुर्नस्थापना परियोजना की पहचान बन चुका मध्य प्रदेश का कूनो नेशनल पार्क एक बार फिर बेहद ऐतिहासिक पल का गवाह बनने जा रहा है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आगामी 21 जून को दो दिवसीय प्रवास पर श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क पहुंचेंगी। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार, राष्ट्रपति 21 जून को दोपहर करीब 3 बजे कूनो पहुंचेंगी और वन्यजीवों के इस खूबसूरत आशियाने के बीच ही रात्रि विश्राम (ओवरनाइट स्टे) करेंगी। इसके बाद 22 जून की सुबह वे पार्क के भीतर विभिन्न

गतिविधियों का अवलोकन करेंगी, जिसके लिए उनका 45 मिनट का एक विशेष कार्यक्रम तय किया गया है।

बोत्सवाना के चीतों को खुले जंगल में मिलने वाली है आजादी- इस दौरे की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक खास बात यह मानी जा रही है कि बोत्सवाना से भारत लाए गए शेष चीतों को राष्ट्रपति के हाथों ही कूनो के खुले जंगल में छोड़ा जा सकता है। दरअसल, जब बोत्सवाना सरकार ने भारत के लिए इन चीतों का चयन किया था, तब प्रतीकात्मक रूप से इन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ही सौंपा गया था। ऐसे में यदि महामहिम खुद इन चीतों को कूनो के बड़े बाड़े से आजाद कर जंगल में छोड़ती हैं, तो यह वैश्विक चीता प्रोजेक्ट के इतिहास में एक बेहद भावुक और महत्वपूर्ण अध्याय साबित होगा।

तैयारियों को लेकर कलेक्टर ने बुलाई हाई-लेवल बैठक- राष्ट्रपति के इस बेहद संवेदनशील और हाई-प्रोफाइल दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद हो गया है। श्योपुर कलेक्टर शीला दाहिमा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर ने लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों को कूनो स्थित हेलिपैड को वीआईपी सुरक्षा मानकों के अनुरूप तत्काल अपग्रेड करने और सभी प्रकार के कड़े प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए हैं। इस महत्वपूर्ण बैठक में जिले के पुलिस अधीक्षक सहित कूनो नेशनल पार्क के तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे।

चिकित्सा शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही

एम्प्लॉई कोड न मिलने से अटके क्लास 3 और 4 कर्मचारियों के ट्रांसफर, छिड़ा बवाल

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत आने वाले सरकारी मेडिकल कॉलेजों के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सामने एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। राज्य सरकार ने कई विभागों के लिए ऑनलाइन ट्रांसफर विंडो तो खोल दी है, लेकिन चिकित्सा शिक्षा विभाग की लापरवाही के कारण हजारों कर्मचारी इसमें आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। दरअसल, ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए एक अनिवार्य 'एम्प्लॉई कोड' की आवश्यकता होती है, जो विभाग ने इन कर्मचारियों को आज तक जारी ही नहीं किया है। इसके चलते वे सिस्टम से पूरी तरह बाहर हो गए हैं।

पेंशन और ग्रेच्युटी पर भी संकट- एमपी मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन (एमटीए) के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राकेश मालवीय ने इस व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने चेतावनी दी कि एम्प्लॉई कोड न होने का असर सिर्फ तबादलों पर ही नहीं पड़ रहा, बल्कि सेवानिवृत्त (रिटायर्ड) हो चुके कर्मचारियों की पेंशन और ग्रेच्युटी मिलने में भी भारी देरी हो रही है। इस गंभीर मुद्दे को लेकर एसोसिएशन के सदस्यों ने पिछले महीने अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) अशोक वर्णवाल से मुलाकात की थी। एसीएस ने कोड जारी करने पर सहमति जताते हुए फाइल को वित्त विभाग के पास भेजा था, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला।

बोलेरो ने 3 लोगों को रौंदा जीजा-साले की मौत

झांसी में पूजा में शामिल होकर बाइक से घर लौट रहे थे, एक की हालत नाजुक

झांसी (नप्र)। झांसी में तेज रफ्तार बोलेरा गाड़ी ने बाइक सवार 3 लोगों को रौंद दिया। हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि एक की हालत नाजुक बनी हुई है। मरने वाले दोनों व्यक्ति रिश्ते में जीजा-साले लगते थे। तीनों धार्मिक पूजा में शामिल होकर बुधवार देर रात बाइक से घर लौट रहे थे। रास्ते में तेज रफ्तार में आ रही बोलेरो गाड़ी ने

बाइक को टक्कर मार दी। प्रीतम अहिरवार (60) की मौके पर ही मौत हो गई। दो घायलों को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया। यहां पर इलाज के दौरान प्रीतम के जीजा प्रेमी अहिरवार (60) ने दम तोड़ दिया। एक घायल की हालत नाजुक बनी है। हादसा रक्सा थाना क्षेत्र के झांसी-शिवपुरी हाइवे पर डगरवाहा गांव के पास हुआ है।

मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के दिनारा थाना क्षेत्र के सेवड़ी गांव निवासी शंकर अहिरवार ने बताया- मेरे गांव के परसुराम अहिरवार के परिवार ने बुधवार को सिमरधा बांध के पास धार्मिक स्थान पर पूजा कराई थी। इसमें गांव के लोगों का खाना था।

ग्वालियर-जबलपुर समेत 34 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट

खजुराहो में 45 डिग्री पर पहुंचा पारा, आज 6 जिलों में ओले गिरने की चेतावनी

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश में प्री-मानसून गतिविधियां तेज हैं। ट्रफ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के असर से प्रदेश में लगातार बारिश और तेज आंधी का दौर जारी है।

बुधवार -गुरुवार को 20 से ज्यादा जिलों में मौसम बदला रहा, ग्वालियर, जबलपुर समेत 34 जिलों में 40 से 60 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले सप्ताह मानसून के सक्रिय होने तक प्री-मानसून का असर बना रहेगा। शुक्रवार को मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर में ओलावृष्टि की भी संभावना है। आंधी-बारिश के बावजूद गर्मी

का असर बना हुआ है। बुधवार को खजुराहो लगातार दूसरे दिन प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ग्वालियर में 43.1 डिग्री, जबलपुर में 40.5 डिग्री, भोपाल में 40.4 डिग्री, उज्जैन में 39.5 डिग्री और इंदौर में 38.9 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया।

मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा के अनुसार, प्रदेश में सक्रिय प्री-मानसून सिस्टम, ट्रफ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण मौसम में यह बदलाव देखने को मिल रहा है। 13 जून को ग्वालियर-चंबल और बुंदेलखंड के कुछ जिलों में तेज आंधी का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है।

आज इन जिलों में अलर्ट- मौसम विभाग के अनुसार, गुरुवार को ग्वालियर, दतिया, मुरैना, भिंड, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, जबलपुर, कटनी, छिंदवाड़ा, सिवनी, नरसिंहपुर, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, पांढुर्णा, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज, मैहर, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, सागर, पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी में आंधी-बारिश होने का अनुमान है।

- **यहां गिर सकते हैं ओले-** मौसम विभाग ने मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर में ओले गिरने का अलर्ट जारी किया है।

यहां पर आंधी की रफ्तार 40 से 60 किमी प्रतिघंटा तक रह सकती है

वहीं इंदौर, धार, आलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, झाबुआ, उज्जैन, नीमच, आगर-मालवा, मंदसौर, शाजापुर, देवास, रतलाम, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, भोपाल, विदिशा, सीहोर और राजगढ़ में गर्मी का असर देखने को मिल सकता है।

मां को फोन लगाकर रोती रही गर्भवती नवविवाहिता

थोड़ी देर बाद ससुराल से आई मौत की खबर

मुरैना (नप्र)। मध्य प्रदेश के मुरैना में एक नवविवाहित महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो घई है। ससुराल पक्ष के लोगों का कहना है कि उसने जान दी है। वहीं, मायके के लोगों का कहना है कि उसकी हत्या हुई है। मां का कहना है कि मौत से पहले उसने कॉल किया था और रोए जा रही थी। पुलिस मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।

रविवार की रात हुई मौत- मृतक रानी पचौरी 24 साल की थी। रविवार को आधी रात को परिजन पोरसा अस्पताल लेकर पहुंचे थे। कहा था कि रानी ने खुदकुशी कर ली है। डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। रानी दो महीने की प्रेग्नेंट थी। रानी पचौरी भिंड जिले के गढ़ गनेरा गांव की रहने वाली थी। मौत की खबर मिलने के बाद परिजन भी वहां पहुंच गए थे।

भाई का है बड़ा आरोप- रानी के भाई अमन पचौरी ने मीडिया से बात करते हुए आरोप लगाया है कि बहन को फंदे पर लटकाकर हत्या की गई है। उसने रोते हुए मां को फोन किया था। वह सिर्फ रोती रही फिर मौत की खबर आई। पहले लोगों ने सूचना दी थी कि रानी को हार्ट अटैक आया है।

पोरसा भागे परिजन- वहीं, मृतक रानी के परिजन भागते हुए रात में ही पोरसा पहुंचे। यहां पहुंचने पर पता चला कि उसकी मौत फंदे पर लटकने से हुई है। भाई ने कहा कि रानी पचौरी की शादी एक साल पहले हुई थी। 17 मई को पहली सालगिरह थी। बातचीत में उसने बताया था कि सालगिरह के बाद लगातार ससुराली लोग बेइज्जत कर रहे थे। जिसकी वजह से वह टूट गई। टीआई, पोरसा ने कहा जौटई रोड पर एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है।

किसान कल्याण वर्ष

मध्यप्रदेश, देश में सब्जी उत्पादन में तीसरे स्थान पर

चार वर्षों में सब्जी उत्पादन में 21.58 लाख मीट्रिक टन की हुई अभूतपूर्व वृद्धि

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश आज कृषि और उद्यानिकी के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में अपनी सशक्त पहचान बना चुका है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, इसका उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि, कृषि का विविधीकरण तथा खेती को अधिक लाभकारी बनाना है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव कहते है कि कृषि को केवल पारंपरिक फसलों तक सीमित नहीं रखा जा सकता। किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि के साथ उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण को भी समान महत्व देना आवश्यक है। विगत 4 वर्ष में प्रदेश के सब्जी उत्पादन में लगभग 21.58 लाख मीट्रिक टन की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। मध्यप्रदेश देश में सब्जियों के उत्पादन में तीसरे स्थान पर है।

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा समृद्ध किसान-समृद्ध मध्यप्रदेश की थीम पर सब्जी क्षेत्र विस्तार की व्यापक कार्ययोजना तैयार की गई है। प्रदेश की अनुकूल जलवायु, उपजाऊ भूमि, सिंचाई संसाधनों का विस्तार तथा किसानों द्वारा आधुनिक तकनीकों को अपनाने के कारण सब्जी उत्पादन में निरंतर वृद्धि दर्ज की जा रही है।

वर्ष 2022-23 में प्रदेश में सब्जियों का उत्पादन 236.41 लाख मीट्रिक टन था, जो वर्ष 2024-25 में बढ़कर 257.99 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गया। यह वृद्धि राज्य के कृषि एवं उद्यानिकी क्षेत्र की सुदृढ़ प्रगति को दर्शाती है।

राष्ट्रीय स्तर पर सब्जियों का कुल उत्पादन लगभग 2177 लाख मीट्रिक टन है, जिसमें मध्यप्रदेश की भागीदारी लगभग 259 लाख मीट्रिक टन है। इससे स्पष्ट है कि देश की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा में मध्यप्रदेश महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। प्रदेश के लाखों किसान सब्जी उत्पादन से अपनी आय भी बढ़ा रहे हैं और देश की बढ़ती मांग को भी पूरा कर रहे हैं। प्रदेश में किसानों द्वारा प्याज, आलू, टमाटर, बैंगन, फूल-गोभी, पत्ता-गोभी, हरी मटर, भिंडी, पालक, लौकी, अरबी, करेला, ककड़ी, मूली, तुरई (तोरी), गाजर, शकरकंद, शिमला मिर्च, परवल सहित अनेक प्रकार की सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। इनमें प्याज उत्पादन का विशेष स्थान है। प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र प्याज की खेती के लिए उपयोग किया जाता है।

वर्ष 2022-23 में प्याज का रकबा 2.17 लाख हेक्टेयर था, जो वर्ष 2024-25 में बढ़कर लगभग 2.30 लाख हैक्टेयर हो गया है। यह वृद्धि किसानों के बढ़ते विश्वास और बाजार में प्याज की मांग को दर्शाती है। प्रदेश में छोटी जोत वाले किसानों को सब्जी फसलों के उत्पादन के लिये ओर प्रोत्साहित किया जाना जरूरी है। जिनसे कम भूमि में अधिक आय प्राप्त हो सके।

एएसआई की बेटी आसमान में भरेगी उड़ान

इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर बनीं प्रिया मालवीय

छिंदवाड़ा (नप्र)। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की रहने वाली प्रिया मालवीय का भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर चयन हुआ है। अब प्रिया आसमान में उड़ान भरेंगी। उन्होंने अपनी इस सफलता से परिवार और क्षेत्रवासियों का मान बढ़ाया है।

ऑनलाइन कोचिंग से की थी तैयारी- प्रिया ने कहा कि एएफसीएटी (एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट) में क्वालीफाई करने के बाद एसएसबी इंटरव्यू होता है। इसके बाद मेडिकल किया जाता है, फिर फाइनल लिस्ट बनाई जाती है। उन्होंने बताया कि एक कोर्स में तकरीबन 300-350 बच्चों को शामिल किया जाता है। इसके साथ ही प्रिया ने कहा कि परीक्षा की तैयारी के लिए मैंने ऑनलाइन कोचिंग की थी। उन्होंने बताया कि मेरे लिए काफी अच्छा अनुभव है। मेरा मानना है कि मैं ही नहीं सभी बेटियां आगे बढ़ें। बेटियां अपना करियर खुद चुनें।

सार्थक हो गया मेरा जीवन- प्रिया मालवीय के पिता रवि मालवीय ने कहा कि मेरी बेटी की इस सफलता पर अंदर से बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। बेटी ने मेरा जीवन सार्थक कर दिया है। जिले में पहली बेटी हैं, जिन्होंने इस पद को हासिल किया है। रवि मालवीय, प्रिया के पिता ने बताया कि कभी ऐसा अवसर ही नहीं आया कि बेटी को डांटना पड़ा हो। मेरी बेटी पढ़ाई के प्रति काफी जागरूक है। उसने अपनी लगन से इस सफलता को हासिल किया है।

एएसआई हैं पिता- छिंदवाड़ा के कोतवाली में एएसआई रवि मालवीय की बेटी प्रिया मालवीय ने वर्ष 2025 में हुए एएफसीएटी एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट में ऑल इंडिया 113वीं रैंक प्राप्त की है। प्रिया जिले की पहली फ्लाइंग ऑफिसर बनी हैं। गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में बीई की डिग्री प्राप्त की।

देश की सेवा करना चाहती है प्रिया- पिता को पुलिस की नौकरी करते देखते हुए बड़ी हुईं बेटी प्रिया भी देश सेवा करना चाहती थीं। सपनों को पूरा करने के लिए शुरुआत में उन्होंने गुजरात से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और बाद में फिर एएफसीएटी एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट दिया। जिसे क्वलिफाई कर अब फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर चयनित हुई हैं। अब प्रिया ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद जाएंगी।

क्योटी वाटर फॉल की खाई में बाइक समेत गिरे दो युवक, नहीं मिले हैं दोनों, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

रीवा (नप्र)। जिले के सिरमौर थाना क्षेत्र स्थित प्रसिद्ध क्योटी जलप्रपात में बुधवार देर शाम एक बड़ा हादसा हो गया। यहां दो युवक बाइक सहित गहरी खाई में जा गिरे। घटना की जानकारी देर रात पुलिस गश्त के दौरान लगी, जिसके बाद प्रशासन और राहत-बचाव दल तत्काल सक्रिय हुआ। रातभर चले रेस्क्यू अभियान के बावजूद युवकों का पता नहीं चल सका है। गुरुवार सुबह से एसडीआरएफ की टीम खाई में उतरकर दोनों युवकों की तलाश में जुटी हुई है।

बाइक समेत क्योटी वाटर फॉल में गिरे- जानकारी के अनुसार बुधवार शाम दो युवक किसी कारणवश क्योटी जलप्रपात के समीप गहरी खाई में बाइक समेत गिर गए। घटना के समय आसपास मौजूद लोगों को इसकी जानकारी नहीं लग सकी। देर रात क्षेत्र में गश्त कर रही पुलिस को हादसे की सूचना मिली, जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराया गया।

रेस्क्यू अभियान जारी- सूचना मिलते ही पुलिस, रीवा प्रशासन और राहत-बचाव दल मौके पर पहुंचा तथा रात में ही रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। हालांकि खाई अत्यधिक गहरी और दुर्गम होने के कारण बचाव कार्य में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अंधेरा और कठिन भू-भाग होने से राहत कार्य की गति भी प्रभावित रही।

एसडीआरएफ के जवान जुटे- गुरुवार सुबह एसडीआरएफ के जवान विशेष उपकरणों के साथ खाई में उतरे और युवकों की तलाश शुरू की। प्रशासन द्वारा लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। फिलहाल दोनों युवकों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है।

मौके पर भारी भीड़- घटना के बाद क्षेत्र में लोगों की भारी भीड़ जुट गई है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने और रेस्क्यू कार्य में सहयोग करने की अपील की है।

जमीन विवाद में दंपत्ति ने जहर खाया, पत्नी की मौत

बेटी बोली- 40 बीघा खेत पर कब्जा करने के लिए ताऊ, ताई और दादी करते थे परेशान

विदिशा (नप्र)। विदिशा जिले के चिडोरिया पड़ायत गांव में 6 साल से चले आ रहे 40 बीघा जमीन के विवाद के चलते एक दंपत्ति ने जहर खा लिया। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां 40 वर्षीय पत्नी मुन्नी बाई दांगी की मौत हो गई, जबकि 45 वर्षीय पति सुरेश दांगी की हालत गंभीर बनी हुई है।

बच्चों ने अपने ही सगे रिश्तेदारों पर माता-पिता को प्रताड़ित करने और आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोप लगाए हैं। 45 वर्षीय पति सुरेश दांगी की हालत गंभीर बनी हुई है।

हार्वेस्टर ले जाने पर बढ़ा था विवाद- मामले की जांच कर रहे एएसआई राधेलाल बड़गड़े के अनुसार, सुरेश दांगी का अपने ही परिवार के सदस्यों के साथ जमीन की हिस्सेदारी और उसके उपयोग को लेकर तनाव चल रहा था। बुधवार को यह विवाद उस समय चरम पर पहुंच गया, जब खेत में हार्वेस्टर ले जाने की बात पर दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया। इससे आहत होकर पति-पत्नी ने घर आकर जहरीला पदार्थ पी लिया। घटना के तुरंत बाद दोनों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां हालत बिगड़ने पर उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। यहां इलाज के दौरान मुन्नी बाई ने दम तोड़ दिया।

बेटा बोला- पुलिस से कई बार शिकायत की- दंपत्ति के बेटे विनीत दांगी ने बताया- हमारे पिता को कई सालों से अपने ही खेतों में खेती नहीं करने दी जा रही थी। जब वे हार्वेस्टर लेकर खेत जा रहे थे, तब विवाद किया गया। हमने इसकी शिकायत कई बार पुलिस और प्रशासन से की, लेकिन किसी ने नहीं सुनी।विनीत ने कहा कि अगर अब भी दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो उनका न्याय व्यवस्था से भरोसा उठ जाएगा।

बेटी ने कहा- ताऊ, ताई और दादी ने बनाया मानसिक दबाव- बेटी अंजली दांगी ने अपने रिश्तेदारों को मां की मौत का जिम्मेदार ठहराया है। अंजली ने आरोप लगाया कि उसके माता-पिता पर ताऊ, ताई, दादी और परिवार के अन्य सदस्य लगातार मानसिक दबाव बना रहे थे। खेत में मारपीट और अपमान से आहत होकर ही उन्होंने यह कदम उठाया। अंजली ने पुलिस से मांग की है कि इन सभी आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए।

चार बच्चों के भविष्य पर संकट, जांच में जुटी पुलिस- सुरेश और मुन्नी बाई के चार बच्चे (तीन बेटियां और एक बेटा) हैं। इनमें से सबसे बड़ी बेटी की हाल ही में शादी हुई है, जबकि बाकी तीनों बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। आंखों के सामने मां का साया उठ जाने और पिता के अस्पताल में होने के कारण इन बच्चों के भविष्य और भरण-पोषण पर संकट खड़ा हो गया है। इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन का कहना है कि घटना की हर पहलू से जांच की जा रही है। जमीन विवाद के पुराने रिकॉर्ड, जहर खाने की मुख्य वजह और प्रताड़ना के आरोपों की पड़ताल की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य और सबूत सामने आएंगे, उसके आधार पर आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।